दैनिक मध्य स्वर्णिम

मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं नई दिल्ली से एक साथ प्रकाशित

नई दिल्ली, मंगलवार 28 जुलाई 2026 सच्ची ख़बर, सबकी ख़बर... वर्ष - 01 अंक-228 पृष्ठ-08 मूल्य-₹01 www.madhyaswarnim.com

मंगल मिलन बैठक में सरकार के विधायी एजेंडे, विपक्ष के विरोध और गठबंधन दलों के बीच समन्वय पर होगी चर्चा

संसद में विपक्ष को घेरने की तैयारी, आज मंगल मिलन बैठक में बनेगी एनडीए की रणनीति

मध्य स्वर्णिम, नई दिल्ली।

संसद के मानसून सत्र के बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) मंगलवार को अपनी संसदीय दल की अहम बैठक करने जा रहा है। मंगल मिलन के नाम से होने वाली यह बैठक सुबह 9:30 बजे संसद पुस्तकालय भवन स्थित जीएमसी बालायोगी सभागार में आयोजित होगी। बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के एनडीए सांसदों के साथ संसद सत्र के दौरान सरकार की रणनीति और गठबंधन के आपसी समन्वय पर चर्चा होने की संभावना है। संसद में भाजपा के कार्यालय सचिव की ओर से एनडीए के सभी लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को बैठक में शामिल होने के लिए सूचना भेजी गई है। नोट में सभी सांसदों से समय पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने का अनुरोध किया गया है। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब संसद के मानसून सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। दूसरी ओर विपक्ष भी छात्रों के प्रदर्शन, कथित पुलिस कार्रवाई और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। बैठक में केंद्र सरकार की ओर से मानसून सत्र के दौरान प्रस्तावित विधेयकों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। सरकार आयकर कानून में संशोधन, एमएसएमई क्षेत्र में सुधार, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने और जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण से जुड़े कानूनों में बदलाव सहित कई विधेयक संसद में पेश करने की तैयारी में है।

सांसदों की भूमिका और बोलने की जिम्मेदारियां भी होंगी तय

सरकार के विधायी एजेंडे पर भी होगी चर्चा

■ इसके अलावा परीक्षा प्रणाली में नकल और पेपर लीक जैसी अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई के लिए प्रस्तावित कानून भी सरकार के प्रमुख एजेंडे में शामिल है। ऐसे में एनडीए सांसदों को इन विधेयकों पर सरकार का पक्ष मजबूती से रखने और विपक्ष के सवालों का जवाब देने की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है।

विपक्ष के हमलों का जवाब देने की तैयारी

■ मानसून सत्र के दौरान विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। छात्रों के आंदोलन और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा भी विपक्ष की रणनीति में अहम माना जा रहा है। ऐसे में एनडीए की बैठक में विपक्ष के संभावित विरोध और सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों पर गठबंधन की साझा रणनीति तैयार की जा सकती है। सांसदों को अलग-अलग विषयों पर सरकार का पक्ष रखने और बहस में सक्रिय भूमिका निभाने की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। मंगल मिलन बैठक को एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक का नया स्वरूप माना जा रहा है। इसका उद्देश्य गठबंधन के घटक दलों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और संसद की कार्यवाही को लेकर साझा रणनीति तैयार करना है।

सहयोगी दलों के बीच समन्वय पर जोर

पांच अहम विधेयकों पर सरकार की नजर

■ बैठक में शिवसेना, एलजेपी, टीडीपी, जेडीयू और अन्य सहयोगी दलों के सांसदों के बीच सदन में बोलने की भूमिका और मुद्दों के वितरण पर भी चर्चा हो सकती है। इससे सरकार को महत्वपूर्ण विधेयकों पर गठबंधन के सभी दलों को एकजुट रखने में मदद मिलेगी। मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार पांच प्रमुख विधेयक पेश करने की तैयारी में है। इनमें आयकर (संशोधन) विधेयक, 2026 और सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 प्रमुख हैं। इसके अलावा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 भी सरकार के एजेंडे में शामिल हैं। इनमें से कुछ विधेयक पहले जारी किए गए अध्यादेशों का स्थान लेने के लिए लाए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार के लिए इन विधेयकों को संसद से पारित कराना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

क्यों अहम है एनडीए की यह बैठक?

■ एनडीए की यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक ओर सरकार संसद में अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में गठबंधन के भीतर बेहतर समन्वय सरकार के लिए बेहद जरूरी है। बैठक में सांसदों को सदन की कार्यवाही के दौरान सक्रिय रहने, विपक्ष के सवालों का जवाब देने और सरकार के पक्ष को प्रभावी ढंग से रखने के लिए रणनीति समझाई जा सकती है। साथ ही सहयोगी दलों की चिंताओं और उनकी प्राथमिकताओं पर भी चर्चा होने की संभावना है। कुल मिलाकर, मंगलवार को होने वाली मंगल मिलन बैठक को मानसून सत्र के अगले चरण के लिए एनडीए की रणनीति तय करने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। बैठक के बाद सरकार और उसके सहयोगी दल संसद में विपक्ष के हमलों का सामना करने और प्रस्तावित विधेयकों को आगे बढ़ाने के लिए एक साझा रणनीति के साथ आगे बढ़ सकते हैं।

सच और अहिंसा से डरती है मोदी सरकार, केन-बेतवा विरोध प्रदर्शन पर बोले राहुल गांधी

मध्य स्वर्णिम, नई दिल्ली।

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के खिलाफ आदिवासियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार सत्य और अहिंसक प्रतिरोध से डरती है। राहुल गांधी का यह बयान मध्य प्रदेश में केन-बेतवा परियोजना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे आदिवासियों पर पुलिस कार्रवाई के बाद सामने आया है। राहुल गांधी ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट के जरिए केन-बेतवा परियोजना के खिलाफ आंदोलन कर रहे आदिवासियों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के आदिवासी जल सत्याग्रह और भूख हड़ताल के जरिए अपनी आवाज उठा रहे थे। उनका आरोप है कि परियोजना के लिए आदिवासियों की जमीन ली गई, लेकिन उन्हें अब तक उचित मुआवजा और सम्मानजनक पुनर्वास नहीं मिला। राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखने वाले लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर अपने अधिकारों की मांग करना लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर नागरिक का अधिकार है। राहुल गांधी ने आदिवासियों को देश का मूल मालिक बताते हुए कहा कि जल, जंगल और जमीन पर पहला अधिकार उन्हीं का है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय का संघर्ष केवल जमीन या मुआवजे का मामला नहीं है, बल्कि उनके अस्तित्व और अधिकारों से जुड़ा हुआ है।

असम में बाढ़ से अब तक 68 लोगों की मौत, 5.24 लाख से ज्यादा प्रभावित

मध्य स्वर्णिम, गुवाहाटी।

असम में बाढ़ की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार जरूर हो रहा है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में संकट अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। बाढ़ और उससे जुड़ी घटनाओं में इस साल अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। सोमवार तक राज्य के पांच जिलों में 5.24 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित बताए गए हैं, जबकि 763 गांव अब भी पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर कृषि भूमि को भी नुकसान पहुंचा है और करीब 48,742 हेक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ है। बाढ़ से प्रभावित जिलों में चराईदेव, शिवसागर और जोरहाट सबसे अधिक प्रभावित बताए जा रहे हैं। चराईदेव में करीब 1.9 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं शिवसागर जिले में 1.5 लाख से अधिक और जोरहाट में करीब 1.4 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इन इलाकों में बड़ी संख्या में गांव अब भी जलभराव की स्थिति से जूझ रहे हैं। प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान तेज किया गया है।

चराईदेव, शिवसागर और जोरहाट में सबसे ज्यादा असर

■ बाढ़ का पानी कम होने के साथ ही प्रशासन का ध्यान अब प्रभावित लोगों तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे को बहाल करने पर है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए चार जिलों में 354 राहत शिविर और सहायता वितरण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इन राहत शिविरों में करीब 37,724 विस्थापित लोगों को आश्रय दिया गया है। प्रशासन की टीमें प्रभावित लोगों को भोजन, पेयजल और अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध कराने में जुटी हैं। बाढ़ का पानी कम होने के बाद भी कई इलाकों में लोगों के सामने घर लौटने और सामान्य जनजीवन बहाल करने की चुनौती बनी हुई है। प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बाढ़ ने असम के बुनियादी ढांचे को भी प्रभावित किया है। कई इलाकों में तटबंधों, सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचने की जानकारी सामने आई है। इससे प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन और राहत सामग्री पहुंचाने में भी मुश्किलें पैदा हुई हैं। बाढ़ का असर केवल इंसानी आबादी तक सीमित नहीं रहा। करीब 88,240 घरेलू पशु और मुर्गियां भी प्रभावित हुई हैं।

आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत 38 भवनों के ध्वस्तीकरण पर कमिश्नर की रोक

मुरादाबाद। मुरादाबाद कमिश्नर ने आरडीए के जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। आदेश के बाद फिलहाल यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। जौहर ट्रस्ट ने आरडीए के आदेश को मंडलायुक्त न्यायालय में चुनौती दी थी। आंदोलन के बीच जौहर

यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत मिली है। रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) की ओर से 38 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने अगली सुनवाई तक राहत देते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही फिलहाल यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। जौहर ट्रस्ट ने आरडीए के ध्वस्तीकरण आदेश को चुनौती देते हुए मंडलायुक्त न्यायालय में वैधानिक अपील दाखिल की थी।

सीजेपी प्रदर्शन के दौरान विदेश से साजिश का दावा एआई-डीपफेक से फैलाया जा रहा था फर्जी प्रचार

मध्य स्वर्णिम, मुंबई।

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शनों के बीच महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने सोशल मीडिया पर कथित तौर पर भारत विरोधी प्रचार और भ्रम फैलाने वाले एक संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक, इस नेटवर्क से जुड़े 500 से अधिक संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान की गई है। इनमें से करीब 100 खाते भारत के बाहर से संचालित किए जा रहे थे। जांच में इन खातों का संबंध पाकिस्तान, मलेशिया और पश्चिम एशिया के कुछ देशों से होने का दावा

किया गया है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस के अनुसार, सीजेपी प्रदर्शनों के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित की जा रही थीं। जांच में 429 आपत्तिजनक पोस्ट और हैंडल चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 140 से अधिक पोस्ट में एआई और डीपफेक तकनीक के इस्तेमाल की बात सामने आई है। पुलिस का दावा है कि एक केंद्रीय मंत्री का वीडियो और ऑडियो भी एआई तकनीक की मदद से तैयार कर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया। इस तरह की सामग्री के जरिए लोगों के बीच भ्रम पैदा करने और माहौल को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने जांच के दौरान फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय संदिग्ध अकाउंट की पहचान की।

आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार जन्म नियंत्रण को लेकर डाली गई थी याचिका

मध्य स्वर्णिम, नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने पशु जन्म नियंत्रण केंद्रों में कुत्तों के प्रति कथित क्रूरता पर दायर याचिका सुनने से इनकार कर दिया। याचिका में एडब्ल्यूबीआई की मान्यता के बिना पशु जन्म नियंत्रण अभियान रोकने की मांग थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) को पशु जन्म नियंत्रण केंद्रों और आश्रयों में कुत्तों के प्रति क्रूरता के मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (ञ्ह्य) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी कि कोई भी नगर निकाय या स्थानीय प्राधिकरण

पशु जन्म नियंत्रण अभियान चलाने के लिए किसी भी पशु कल्याण संगठन को तब तक नियुक्त न करे जब तक कि उसके पास ड्ड्ब्ल्ह्ल से वैध परियोजना मान्यता प्रमाण पत्र न हो। पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 के अनुसार, आवारा कुत्तों के लिए कोई भी पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम तब तक संचालित नहीं किया जाएगा जब तक कि स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संगठन को नियमों के तहत ऐसे कार्यक्रम के संचालन के लिए परियोजना मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त न हो जाए। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ को परियोजना मान्यता प्रमाण पत्र के बारे में बताया। वकील ने शीर्ष अदालत के 19 मई के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें कई निर्देश दिए गए थे, जिनमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पशु जन्म नियंत्रण ढांचे के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए समयबद्ध कदम उठाने के लिए कहना शामिल था। याचिका में यह निर्देश देने की भी मांग की गई थी कि सभी पशु कल्याण संगठन जिन्होंने एडब्ल्यूबीआई से अपनी परियोजना मान्यता का नवीनीकरण प्राप्त नहीं किया है, उन्हें अपनी परियोजना मान्यता का वैध नवीनीकरण प्राप्त होने तक किसी भी प्रकार के पशु जन्म नियंत्रण

प्रश्नपत्र तैयार करने वालों की ईमानदारी होगी सबसे बड़ी चुनौती

चेन्नई। देश में पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाने और परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह सुरक्षित बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने सुधार प्रक्रिया तेज कर दी है। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्य और आईआईटी

मद्रास के निदेशक वी. कामकोटी ने सोमवार को कहा कि परीक्षा प्रणाली को लीक-प्रूफ बनाने के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रश्नपत्र तैयार करने वाले लोगों की ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि किसी भी परीक्षा व्यवस्था की सफलता केवल तकनीक पर निर्भर नहीं करती। इसके लिए उन लोगों पर भरोसा होना भी जरूरी है, जो प्रश्नपत्र तैयार करते हैं और परीक्षा केंद्रों पर पूरी प्रक्रिया की निगरानी करते हैं।

एंकर

20 बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग

खतरे में टहएमसी के बागी सांसदों की कुसी : अभिषेक बनर्जी ने ओम बिरला से की मुलाकात, स्पीकर के फैसले पर टिकी नजरें

मध्य स्वर्णिम, नई दिल्ली।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर शुरू हुआ सियासी विवाद अब संसद तक पहुंच गया है। पार्टी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसदों के बागी गुट में शामिल होने के दावे के बीच टीएमसी संसदीय दल के प्रमुख अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि करीब 20 मिनट तक चली बैठक में अभिषेक बनर्जी ने बागी सांसदों की सदस्यता समाप्त करने और उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग उठाई। बंगाल चुनाव में पार्टी की हार के बाद टीएमसी में अंदरूनी कलह तेज हो गई। इसके बाद पार्टी के 28 में से 20 लोकसभा सांसदों ने अलग रुख अपनाते हुए त्रिपुरा की राष्ट्रवादी सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में अपने गुट के विलय का ऐलान किया। बागी सांसदों की ओर से दावा किया जा रहा है कि दो-तिहाई से अधिक सांसदों के एक साथ

अलग होने के कारण उन पर दल-बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। हालांकि, इस विलय को लेकर अंतिम फैसला अभी लोकसभा अध्यक्ष को करना है। यही वजह है कि बागी सांसदों की सदस्यता और उनकी संसदीय स्थिति को लेकर सियासी और कानूनी पेंच बना हुआ है। अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात के दौरान बागी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। टीएमसी का तर्क है कि इन सांसदों ने पार्टी से अलग होकर दल-बदल किया है और उन्हें सांसद पद से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी के बचे हुए आठ सांसदों के लिए सदन में बैठने की व्यवस्था से जुड़ी मांग भी रखी। पार्टी की कोशिश है कि बागी सांसदों के दावे को कानूनी मान्यता न मिले और टीएमसी के मूल दल की संसदीय स्थिति बरकरार रहे। लोकसभा अध्यक्ष ने फिलहाल 20 बागी सांसदों की बैठने की व्यवस्था टीएमसी के मूल गुट से अलग कर दी है।

बागी सांसदों के विलय को लेकर कानूनी पेंच

■ हालांकि, यह कदम बागी सांसदों के विलय को अंतिम कानूनी मान्यता देने के बराबर नहीं माना जा रहा है। उनके विलय और सदस्यता को लेकर स्पीकर की अंतिम मंजूरी अभी बाकी है। इस वजह से संसद के मानसून सत्र के दौरान टीएमसी के भीतर की यह टूट सदन में भी साफ दिखाई दे रही है। एक तरफ 20 सांसदों का बागी गुट है, जबकि दूसरी ओर पार्टी के आठ सांसद टीएमसी के मूल गुट के साथ हैं। संसद के मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में भी टीएमसी के बागी सांसदों और NCPI के मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों में नाराजगी देखने को मिली थी। विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया था कि जब तक लोकसभा अध्यक्ष की ओर से NCPI में विलय को आधिकारिक मान्यता नहीं दी गई है, तब तक उसे सर्वदलीय बैठक में अलग राजनीतिक दल के तौर पर आमंत्रित करना उचित नहीं है।

पुलिस कार्रवाई का मुद्दा संसद में उठाने की तैयारी

बिहार में छात्रों पर एके-47 के इस्तेमाल का दावा, पवन खेड़ा ने सरकार को घेरा; शाह से संसद में बयान और माफी की मांग

मध्य स्वर्णिम, नई दिल्ली।

परीक्षा पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे युवाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि बिहार के सीवान में छात्रों के खिलाफ एके-47 तक का इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद में बयान देने और माफी मांगने की मांग की है। पवन खेड़ा ने कहा कि विपक्ष लगातार संसद में युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि छात्र सीधे तौर पर अपनी बात सदन में नहीं रख सकते, इसलिए विपक्ष उनकी आवाज संसद तक पहुंचाने का काम कर रहा है। खेड़ा के मुताबिक, जब तक सरकार छात्रों की शिकायतों और उनके प्रदर्शन से जुड़े मुद्दों पर जवाब नहीं देती, तब तक संसद में जारी गतिरोध खत्म होना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की मांग स्पष्ट है कि सरकार को छात्रों के साथ हुई कथित कार्रवाई पर सदन में जवाब देना चाहिए। कांग्रेस नेता ने केंद्रीय गृह मंत्री

अमित शाह से राज्यसभा में आकर पूरे मामले पर बयान देने की मांग की। उन्होंने कहा कि देशभर में प्रदर्शन कर रहे युवाओं से जुड़े गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं और ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह संसद में स्थिति स्पष्ट करे। खेड़ा ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की समस्याओं को सुनने के बजाय उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष युवाओं के मुद्दे को लगातार संसद में उठाता रहेगा और सरकार से जवाब मांगता रहेगा। पवन खेड़ा ने बिहार के सीवान का जिक्र करते हुए दावा किया कि वहां छात्रों के खिलाफ एके-47 तक का इस्तेमाल किया गया।

ढाबों पर आबकारी विभाग का सघन अभियान, 23 प्रकरण दर्ज

बिना लाइसेंस मदिरा परोसने और सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई

मध्य स्वर्णिम, इंदौर।

कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन एवं सहायक आबकारी आयुक्त अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा विशेष अभियान के तहत 25 जुलाई को शहर और बायपास क्षेत्र के विभिन्न ढाबों पर सघन जांच अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य बिना लाइसेंस मदिरा परोसने और सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान जैसी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना था। कार्रवाई के दौरान आबकारी विभाग की टीम ने विभिन्न ढाबों पर दबिश देकर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 36(ए) एवं 36(बी) के तहत कुल 23 प्रकरण दर्ज किए। इस दौरान 23 व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई।

चार ढाबों पर 10 प्रकरण दर्ज

■ भोई मोहल्ला क्षेत्र स्थित मेट्रो ढाबा, पंजतारा ढाबा, गामा दा ढाबा एवं चस्का ढाबा पर भी आबकारी विभाग ने कार्रवाई की। यहां खुले में मदिरापान करते पाए गए व्यक्तियों और संचालकों के विरुद्ध कुल 10 प्रकरण दर्ज किए गए। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध मदिरा विक्रय, बिना लाइसेंस मदिरा परोसने और सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान जैसी गतिविधियों के खिलाफ विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। विभाग ने आमजन से आबकारी कानूनों का पालन करने की अपील करते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की जानकारी संबंधित विभाग को उपलब्ध कराएं।

पंजाबी ढाबा और पप्पू ढाबा पर कार्रवाई

रिंग रोड स्थित पप्पू ढाबा पर जांच के दौरान खुले में मदिरापान करते पाए गए व्यक्तियों और ढाबा संचालक के विरुद्ध धारा 36(ए) एवं 36(बी) के तहत कुल 5 प्रकरण दर्ज किए गए। बायपास स्थित ग्रिलीशियस ढाबे पर कार्रवाई के दौरान खुले में मदिरापान करते पाए गए व्यक्तियों और संचालक के विरुद्ध कुल 4 प्रकरण दर्ज किए गए। बायपास स्थित अर्बन तड़का एवं सफारी ढाबों पर आबकारी विभाग की टीम ने दबिश दी। यहां खुले में मदिरापान करते पाए गए व्यक्तियों और ढाबा संचालकों के विरुद्ध कुल 4 प्रकरण दर्ज किए गए।

ग्रिलीशियस ढाबे पर 4 प्रकरण

कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी जय सिंह ठाकुर एवं बबिता शिंदे, आबकारी उप निरीक्षक त्रिअंबिका शर्मा, आशीष जैन, सुनील मालवीय सहित आबकारी विभाग का अमला उपस्थित रहा।

अपराधियों जैसा व्यवहार करने का दावा; अपशब्द कहने और मानसिक प्रताड़ना के आरोप

नीट पेपर लीक विरोध में गिरफ्तार छात्रों के गंभीर आरोप, बातचीत के बहाने बुलाकर जेल भेजा

मध्य स्वर्णिम, इंदौर।

नीट पेपर लीक के विरोध में 23 जुलाई को इंदौर में प्रस्तावित 'न्याय यात्रा' से पहले गिरफ्तार किए गए छह छात्र नेताओं ने रिहाई के बाद पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्र नेताओं का कहना है कि उन्हें डीसीपी से बातचीत कराने के नाम पर बुलाया गया और बाद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 151 के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया, अपशब्द कहे और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। छात्र नेताओं के अनुसार, पुलिस ने उनके मोबाइल फोन भी अपने कब्जे में ले लिए थे। उनका आरोप है कि करीब चार दिनों तक उनके परिवारों को उनकी स्थिति और ठिकाने की जानकारी नहीं दी गई, जिससे परिजन परेशान रहे। हालांकि, इन आरोपों पर पुलिस का पक्ष सामने आना अभी बाकी है। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के राधे जाट ने बताया कि पुलिस की ओर से उन्हें यह कहकर बुलाया गया था कि न्याय यात्रा को लेकर डीसीपी से चर्चा कराई जाएगी।

इसी भरोसे पर वह पुलिसकर्मियों के साथ चले गए। उनका आरोप है कि रास्ते में उनके मोबाइल फोन बंद करवा दिए गए। इसके बाद उन्हें पहले जिला अस्पताल चौकी और फिर चंदन नगर थाने ले जाया गया। राधे जाट के मुताबिक, अगले दिन मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उन्हें एसीपी जूनी इंदौर के समक्ष पेश किया गया और इसके बाद जेल भेज दिया गया। राधे जाट ने दावा किया कि छात्र संगठनों ने न्याय यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन को पहले ही जानकारी दे दी थी। उन्होंने कहा कि यात्रा से एक दिन पहले पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर अनुमति मांगी गई थी और एसीपी को प्रस्तावित यात्रा की पूरी रूपरेखा भी बताई गई थी। उनके अनुसार, यात्रा में करीब 10 हजार लोगों के शामिल होने की संभावना थी। रिहा हुए छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सुरेंद्र यादव के साथ पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।

'डीसीपी से चर्चा' के नाम पर बुलाने का आरोप

■ छात्रों का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे युवाओं के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया। इस मामले में विजय चौधरी, चंद्रशेखर गुर्जर, गौरव परिहार और हरिप्रपन्न गोस्वामी सहित छह छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने की बात सामने आई है। छात्र नेताओं का आरोप है कि गिरफ्तारी के बाद करीब चार दिनों तक उनके परिवारों को यह जानकारी नहीं दी गई कि वे कहां हैं। इससे उनके परिजन काफी परेशान रहे। रिहाई के समय उनसे बॉन्ड ओवर भी भरवाया गया छात्र नेताओं का कहना है कि उन्होंने इससे पहले भी एमपीपीएससी, पटवारी भर्ती घोटाले और अन्य छात्र आंदोलनों में हिस्सा लिया है, लेकिन उनके अनुसार पहले कभी इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई। रिहा हुए छात्र नेताओं ने इंदौर में लागू कमिश्नरी व्यवस्था और धारा 151 के कथित दुरुपयोग की समीक्षा करने की मांग की है।

ब्रेन डेड आर्टिस्ट के परिवार का जज्बा

अहमदाबाद के युवक में धड़केगा इंदौर के गौरव का दिल

मध्य स्वर्णिम, इंदौर

किसी भी माता-पिता के लिए अपने जवान बेटे को खोने से बड़ा दुख शायद ही कोई हो। लेकिन खजूरी बाजार निवासी सतीश दवे और कविता दवे ने 25 वर्षीय बेटे गौरव दवे को खोने के असहनीय दर्द के बीच ऐसा निर्णय लिया, जिसने कई परिवारों की जिंदगी में नई उम्मीद जगा दी। परिवार की सहमति से गौरव के हृदय, लिवर, दोनों किडनियों और नेत्रों का दान किया गया। इस प्रक्रिया के लिए सोमवार को इंदौर में 68वां ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। गौरव फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग को-ऑर्डिनेटर के रूप में कार्यरत थे। 13 जुलाई को उन्हें अचानक ब्रेन हेमरेज हुआ, जिसके बाद उन्हें राजश्री अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने इलाज किया, लेकिन उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। निर्धारित चिकित्सा प्रक्रिया के तहत दो बार परीक्षण के बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया। ब्रेन डेथ की पुष्टि के बाद गौरव की बहन वैदेही राठी, बहनोई पल्केश राठी और भाई रितिक चावरे ने परिवार को अंगदान के लिए प्रेरित किया। बेटे को खोने के गहरे दुख के बावजूद माता-पिता ने समाजहित को प्राथमिकता देते हुए अंगदान की सहमति दी। उनके इस फैसले ने कई गंभीर मरीजों को नई जिंदगी देने का रास्ता खोल दिया अंगदान की पूरी प्रक्रिया में मुस्कान ग्रुप पारमार्थिक ट्रस्ट के सेवादार जीतू बगानी, संदीपन आर्य और लकी खत्री ने परिवार का सहयोग किया। संदीपन आर्य ने बताया कि डॉक्टरों ने परिवार को ब्रेन डेथ और अंगदान की पूरी प्रक्रिया समझाई, जिसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर अंग प्रत्यारोपण की प्रक्रिया शुरू की गई। अंगदान के तहत गौरव का लिवर राजश्री अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती 42 वर्षीय मरीज को प्रत्यारोपित किया गया। उनका हृदय ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से अहमदाबाद स्थित यूएन मेहता हॉस्पिटल भेजा गया, जहां 28 वर्षीय युवक को प्रत्यारोपित किया जाएगा।

नर्मदा में बहा इंदौर का युवक, पत्नी-भाई चीखते रहे; कुछ सेकंड में तेज बहाव में हुआ ओझल

मध्य स्वर्णिम, इंदौर।

खरगोन जिले के महेश्वर स्थित सहस्त्रधारा घाट पर रविवार शाम एक दर्दनाक हादसे में इंदौर का 30 वर्षीय युवक अर्पित हाड़ा नर्मदा नदी के तेज बहाव में बह गया। घटना के समय उसकी पत्नी और भाई भी मौके पर मौजूद थे। युवक को बहता देख दोनों ने मदद के लिए चीख-पुकार मचाई, लेकिन देखते ही देखते अर्पित तेज धारा में कुछ ही सेकंड में ओझल हो गया। हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक के तेज बहाव में बहने का दृश्य दिखाई दे रहा है। घटना की सूचना मिलते ही महेश्वर पुलिस, होमगार्ड की रेस्क्यू टीम और स्थानीय गोताखोर मौके पर पहुंचे। रविवार शाम से देर रात तक नदी में युवक की तलाश की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। सोमवार सुबह करीब 6 बजे से पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम ने नावों की मदद से दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया।

परिवार के साथ घूमने आया था युवक

■ अर्पित हाड़ा इंदौर के निपानिया क्षेत्र का रहने वाला था। वह परिवार के अन्य सदस्यों के साथ महेश्वर और आसपास के पर्यटन स्थलों पर घूमने आया था। रविवार दोपहर करीब 1 बजे परिवार इंदौर से रवाना हुआ था। महेश्वर में दर्शन और भ्रमण के बाद शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच परिवार जलकोटी स्थित सहस्त्रधारा पहुंचा था। बताया जा रहा है कि नर्मदा नदी में स्नान करने के दौरान अचानक अर्पित का पैर फिसल गया। वह गहरे पानी में चला गया और तेज बहाव की चपेट में आ गया। परिवार के लोगों ने उसे बचाने के लिए शोर मचाया, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि कोई भी तत्काल पानी में उतरने की हिम्मत नहीं कर सका।

नारखेड़ी रोड एक साल से जर्जर, हजारों वाहन गुजर रहे

धार। धार शहर का सुनारखेड़ी मार्ग पिछले एक साल से अधिक समय से खराब हालत में है। इंदौर-दाहोद रेल परियोजना के तहत नागदा-गुजरी रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के कारण इस सड़क का उपयोग वैकल्पिक मार्ग के रूप में किया जा रहा है। रोजाना हजारों वाहन इस रास्ते से गुजरते हैं, जिससे सड़क पूरी तरह जर्जर हो गई है। जगह-जगह बारिश का पानी भरा सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं। बारिश के दौरान इनमें पानी भर जाता है। इससे वाहन चालकों को गड्ढों का अंदाजा नहीं लग पाता। सबसे ज्यादा परेशानी दोपहिया वाहन चालकों को होती है। कई बार वाहन फिसल जाते हैं, जिससे हादसों का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की हालत पिछले एक साल से ऐसी ही है, लेकिन अब तक इसकी स्थायी मरम्मत नहीं कराई गई। इसी मार्ग से रोजाना हजारों लोग स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और अपने कार्यस्थल तक पहुंचते हैं।

एसीपी ने जांच के दिए निर्देश

आरोपियों के जुलूस के बाद जेल गेट पर खोले पट्टे, पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल

मध्य स्वर्णिम, इंदौर।

हीरानगर थाना पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। मेडिकल दुकान के बाहर कार और बाइक की टक्कर के बाद हुए विवाद के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। रविवार को पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला। इस दौरान उनके हाथ और पैरों पर पट्टे बांधे गए थे। बाद में आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। देर रात सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें जेल गेट के बाहर आरोपी अपने हाथ और पैरों में बंधे पट्टे खोलते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। हालांकि, वीडियो की वास्तविकता और इससे जुड़े दावों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस के अनुसार, गुरुवार को मेडिकल दुकान के बाहर कार और बाइक की टक्कर के बाद विवाद हुआ था। मामले में पुलिस ने शोभित साक्यवार, निक्की अहिरवार, ओम उर्फ देवाय और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया। इनमें एक आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों का इलाके में जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान आरोपियों के हाथ और पैरों पर पट्टे बंधे हुए दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। रविवार देर रात सामने आए कथित वायरल वीडियो में जेल गेट के बाहर आरोपी अपने हाथ और पैरों से पट्टे खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि आरोपियों के हाथ-पैर में पट्टे केवल दिखावे के लिए बांधे गए थे और बाद में उन्हें जेल गेट के बाहर खोल दिया गया।

आरआरकैट का इलेक्ट्रॉनिक बूम बैरियर तोड़कर परिसर में घुसी कार

मध्य स्वर्णिम, इंदौर।

राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र स्थित आरआरकैट के मुख्य प्रवेश द्वार पर रविवार देर रात एक कार चालक ने इलेक्ट्रॉनिक बूम बैरियर तोड़कर जबरन परिसर में प्रवेश कर लिया। घटना में शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि चालक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उसका उपचार चल रहा है। राजेंद्र नगर पुलिस ने आरआरकैट निवासी वसंत कुमार कुमरे की शिकायत पर कार क्रमांक एमपी-09-सीएस-8622 के चालक सारिम जफर मंसूरी, निवासी ग्रीन पार्क कॉलोनी, के खिलाफ शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार रविवार रात करीब 12:30 बजे कैट चौराहे पर वाहनों की चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान पुलिस जांच से बचने के प्रयास में सारिम कार लेकर आरआरकैट परिसर की ओर पहुंच गया। उसने मुख्य प्रवेश द्वार पर लगे इलेक्ट्रॉनिक बूम बैरियर को तोड़ दिया और कार लेकर परिसर के अंदर प्रवेश कर गया। बैरियर टूटने से शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा। घटना के बाद आरआरकैट के सुरक्षा गार्ड कार के पीछे दौड़े। कुछ दूरी पर चालक ने वाहन रोक दिया। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया। थाने में पूछताछ के दौरान सारिम पुलिस के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद पुलिस ने उसके मोबाइल फोन से परिजनों से संपर्क किया। परिजनों ने पुलिस को बताया कि सारिम की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उसका उपचार चल रहा है। परिवार के अनुसार, इसी वजह से उसे कोई काम भी नहीं करने दिया जाता है। परिजनों ने उपचार से संबंधित दस्तावेज भी पुलिस को उपलब्ध कराए हैं।

नशे के विरुद्ध इंदौर की ऐतिहासिक हुंकार, 8100 से अधिक नागरिकों ने लिया जागरूकता का संकल्प

मध्य स्वर्णिम, इंदौर।

युवाओं और समाज को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने तथा स्वस्थ, सुरक्षित और नशामुक्त समाज के निर्माण के उद्देश्य से इंदौर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा संचालित नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत रविवार सुबह नेहरू स्टेडियम से रन फॉर ए हेल्दी लाइफस्टाइल से नो टू ड्रग्स जागरूकता मैराथन का भव्य आयोजन किया गया। जन-जागरूकता के इस बड़े अभियान में 8100 से अधिक नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर नशामुक्त समाज के निर्माण का सशक्त संदेश दिया। मैराथन में पुलिस आयुक्त इंदौर संतोष कुमार सिंह की विशेष मौजूदगी रही। भारतीय क्रिकेटर रजत पाटीदार ने भी मैराथन में दौड़ लगाकर युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया।

स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की अपील की

■ मैराथन दो श्रेणियों में आयोजित की गई। पहली 5 किलोमीटर की दौड़ नेहरू स्टेडियम से होल्कर कॉलेज होते हुए वापस नेहरू स्टेडियम पहुंची, जबकि 10 किलोमीटर की दौड़ नेहरू स्टेडियम से राजीव गांधी प्रतिमा तक जाकर वापस स्टेडियम पहुंची।

हर वर्ग ने बढ़-चढ़कर लिया हिस्सा

ऐतिहासिक आयोजन में शहर के युवा, महिलाएं, बच्चे और वरिष्ठ नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विद्यार्थियों, खेल अकादमियों के खिलाड़ियों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रशिक्षु आरक्षकों तथा पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी मैराथन में सहभागिता की। आयोजन ने सामाजिक सहभागिता और जन-जागरूकता की एक मिसाल पेश की। मैराथन शुरू होने से पहले पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने भारतीय क्रिकेटर रजत पाटीदार और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में सभी प्रतिभागियों को नशे से दूर रहने तथा समाज को नशामुक्त बनाने का सामूहिक संकल्प दिलाया।

नशा व्यक्ति के साथ परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है : पुलिस आयुक्त

पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता, बल्कि परिवार की खुशियों, सामाजिक समरसता और राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य पर भी इसका गंभीर असर पड़ता है। उन्होंने नागरिकों से स्वयं नशे से दूर रहने और अपने आसपास के लोगों को भी नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नशामुक्त समाज का निर्माण केवल पुलिस या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें समाज के प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। सामूहिक जागरूकता और सामाजिक सहयोग से ही युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाया जा सकता है।

इस्तीफा सिर्फ शुरुआत, अब शिक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद : सोनम वांगचुक

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले वांगचुक- परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने की जरूरत

मध्य स्वर्णिम, नई दिल्ली।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और हालिया शिक्षा एवं परीक्षा विवादों को लेकर शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रधान के इस्तीफे को सकारात्मक बदलाव की दिशा में पहला कदम बताया। वांगचुक ने कहा कि केवल किसी मंत्री का इस्तीफा समस्या का अंतिम समाधान नहीं है, बल्कि इसके बाद शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में जरूरी सुधार किए जाना सबसे महत्वपूर्ण है। वांगचुक ने कहा कि %इस्तीफा तो बस एक शुरुआत है।% यदि इस बिंदु से आगे बढ़कर समस्याओं को स्वीकार किया जाए और उनके स्थायी समाधान की दिशा में काम किया जाए तो देश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार और संबंधित पक्षों के बीच सकारात्मक संवाद के जरिए ऐसी व्यवस्था विकसित की जाएगी, जिससे देश की परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद बन सके। छात्रों और युवाओं के आंदोलन को लेकर वांगचुक ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। सरकार और प्रशासन को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों और युवाओं की आवाज सुननी चाहिए तथा उनके अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हालांकि, यदि कोई शरारती तत्व दुर्भावना से कानून तोड़ता है या हिंसा जैसी गतिविधियों में शामिल होता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने वाले नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना लोकतांत्रिक व्यवस्था की जिम्मेदारी है। वांगचुक ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार केवल कठोर कानून बनाने से संभव नहीं होगा। इसके लिए सरकार, शिक्षाविदों, छात्रों, अभिभावकों और विशेषज्ञों के बीच लगातार संवाद होना जरूरी है।

सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक पर गंभीर चर्चा की जरूरत

■ सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक को लेकर भी सोनम वांगचुक ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि किसी भी बड़े बदलाव या सुधार से पहले इस विषय पर व्यापक चर्चा और गंभीर विचार-विमर्श होना जरूरी है। सभी संबंधित पक्षों की राय को ध्यान में रखकर ही कोई उचित निर्णय लिया जाना चाहिए।

सरकार से समझौते के उल्लंघन का आरोप, बिहार-बंगाल में छात्रों की गिरफ्तारी और दिल्ली में निगरानी का दावा

सीजेपी का सरकार को अल्टीमेटम, वादे के बावजूद पुलिस कार्रवाई का आरोप

कल तक लिखित आश्वासन देने की मांग

■ उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों को वापस लेने और गिरफ्तार छात्रों को रिहा करने पर सहमति बनी थी। इसके बावजूद यदि मामले वापस नहीं लिए जाते हैं तो छात्रों और आंदोलन से जुड़े लोगों में असंतोष बढ़ सकता है। सीजेपी की ओर से सरकार के सामने प्रदर्शनकारियों से जुड़े कानूनी मामलों को तत्काल खत्म करने की मांग रखी गई है। संगठन का कहना है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर वापस ली जाएं और गिरफ्तार किए गए छात्रों को बिना किसी देरी के रिहा किया जाए। इसके साथ ही सीजेपी ने मांग की है कि दिल्ली पुलिस, केंद्रीय जांच एजेंसियों और भाजपा गठबंधन वाली राज्य सरकारों की पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भविष्य में कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं की जाए। संगठन का कहना है कि यह मांग पहले हुए समझौते के अनुरूप है और सरकार को इसका पालन करना चाहिए। आशुतोष रांका ने सरकार से कानूनी मामलों की वापसी को लेकर हुए समझौते का लिखित मसौदा साझा करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को तय समय-सीमा के अनुसार मंगलवार तक लिखित आश्वासन देना चाहिए, ताकि प्रदर्शनकारियों को यह स्पष्ट हो सके कि उनके खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।

मध्य स्वर्णिम, नई दिल्ली।

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने सरकार पर प्रदर्शनकारियों के साथ हुए कथित समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए एक बार फिर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के साथ बातचीत के दौरान यह तय हुआ था कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद छात्रों की गिरफ्तारी और उन्हें परेशान किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। रांका ने आरोप लगाया कि बिहार और बंगाल में बड़ी संख्या में छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दिल्ली और अन्य राज्यों में प्रदर्शन से जुड़े छात्रों और कार्यकर्ताओं की निगरानी की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों तक भोजन, पानी और अन्य जरूरी सामान पहुंचाने वाले कुछ स्वयंसेवकों को भी हिरासत में लिया गया है। सीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि सरकार के साथ हुए समझौते में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करने का भरोसा दिया गया था। उनके अनुसार, इस समझौते के बावजूद यदि गिरफ्तारियां और पुलिस कार्रवाई जारी रहती है तो यह सरकार की ओर से किए गए वादे का गंभीर उल्लंघन है।

समझौते का पूरी तरह पालन नहीं होने का आरोप

■ सीजेपी का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन पर्याप्त नहीं है। संगठन सरकार से लिखित रूप में यह स्पष्ट करने की मांग कर रहा है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को किस समय-सीमा में वापस लिया जाएगा और गिरफ्तार छात्रों की रिहाई कब तक सुनिश्चित होगी। रांका ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं रोकी गई और समझौते के तहत किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया तो सीजेपी के पास दोबारा बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि संगठन सरकार के साथ हुए समझौते का सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि सरकार भी अपने वादों को पूरा करेगी। लेकिन यदि छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई जारी रहती है तो सीजेपी फिर से धरना और विरोध प्रदर्शन शुरू करने पर विचार करेगी। सीजेपी की इस चेतावनी के बाद एक बार फिर छात्र आंदोलन और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों का मुद्दा चर्चा में आ गया है। अब निगाहें सरकार की ओर हैं कि वह संगठन की मांगों पर क्या कदम उठाती है और कथित समझौते को लागू करने के लिए क्या कार्रवाई करती है।

पेपर लीक के खिलाफ प्रस्तावित कानून की सीएम रेखा गुप्ता ने की तारीफ

मध्य स्वर्णिम, नई दिल्ली।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पेपर लीक और परीक्षा में होने वाली अनियमितताओं के खिलाफ केंद्र सरकार की ओर से उठाए जा रहे सख्त कदमों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत का युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और उसके सपनों, मेहनत और भविष्य की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को निष्पक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद शिक्षा एवं परीक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी गंभीर अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई के लिए मजबूत कानूनी प्रावधान किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना है, ताकि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ न हो सके। सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में कहा कि पेपर लीक मामलों में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित कानून के तहत दोषियों को 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा दोषियों की संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान होने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसा सख्त कानून बनाना है, जिससे भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी तरीके से रोक लगाई जा सके। उन्होंने दावा किया कि परीक्षा में होने वाली अनियमितताओं के खिलाफ सरकार की कार्रवाई से विद्यार्थियों और अभिभावकों में परीक्षा व्यवस्था को लेकर भरोसा मजबूत होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि इन अदालतों में मामलों का तेजी से निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि परीक्षा में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था में भी बदलाव किए जा रहे हैं।

टाइफाइड का दुर्लभ मामला : युवती के कूल्हे तक पहुंचा संक्रमण

मध्य स्वर्णिम, नई दिल्ली।

टाइफाइड का कारण बनने वाला बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी आमतौर पर तेज बुखार, पेट दर्द और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं के लिए जाना जाता है। लेकिन दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इसका एक दुर्लभ मामला सामने आया, जिसमें इस बैक्टीरिया ने एक स्वस्थ 22 वर्षीय युवती के कूल्हे के जोड़ को संक्रमित कर दिया। डॉक्टरों ने समय रहते संक्रमण की पहचान कर एंटीबायोटिक उपचार शुरू किया, जिससे युवती की हालत में सुधार हुआ और सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। युवती को करीब दो सप्ताह से पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, जी मिचलाने, भूख न लगने और तेज बुखार की शिकायत थी। इलाज के दौरान उसके बाएं कूल्हे में अचानक तेज दर्द शुरू हो गया। दर्द इतना बढ़ गया कि उसे चलने-फिरने में भी परेशानी होने लगी। उसका बुखार 104 डिग्री फारेनहाइट से अधिक पहुंच गया और शरीर में तेज कंपकंपी भी होने लगी। इसके बाद डॉक्टरों ने एमआरआई जांच कराई। इसमें कूल्हे के आसपास संक्रमण और सूजन की पुष्टि हुई। डॉक्टरों को आशंका थी कि यदि संक्रमण तेजी से बढ़ा तो कूल्हे के जोड़ को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है और मरीज को सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। युवती के ब्लड कल्चर की जांच में साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की पुष्टि हुई। इसके बाद डॉक्टरों ने हर 12 घंटे में नस के जरिए एंटीबायोटिक सेफ्ट्रिएक्सोन देना शुरू किया।

जांच में खून में संक्रमण के संकेत मिले

■ वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एवं सफदरजंग अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की डॉक्टर रुचिका सक्सेना के अनुसार, जांच के दौरान युवती के शरीर में संक्रमण के संकेत मिले। ब्लड टेस्ट में सफेद रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ी हुई थी।

जंतर मंतर का आंदोलन खत्म, जेन-जी मना रही है जीत का डिजिटल जश्न

मध्य स्वर्णिम, नई दिल्ली।

पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुए छात्र आंदोलन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर जेन-जी का अंदाज सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। रविवार को एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक समेत तमाम प्लेटफॉर्म मीम्स, रील्स, इमोजी और व्यंग्यात्मक पोस्ट से भर गए।

आंदोलन की सबसे अलग पहचान बना कॉकरोच इमोजी, जिसे हजारों युवाओं ने जीत और संघर्ष के प्रतीक के रूप में साझा किया सोशल मीडिया पर सबसे यादा चर्चा मेला बाबू कितना प्याला है... मीम की रही। इसके अलावा गेमिंग स्टाइल कैप्शन, इंटरनेट स्लैंग और मजाकिया पोस्ट लगातार ट्रेंड करते रहे। आंदोलन के दौरान युवाओं ने पारंपरिक नारों की बजाय मीम कल्चर को अपना हथियार बनाया। यही वजह रही कि विरोध सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लगातार छाया रहा। सबसे यादा वायरल हुए नारों में हम कॉकरोच हैं, हम नहीं मरते, कॉकरोच की जीत, एक इस्तीफा और कई बाकी, पेपर लीक बंद करो, शिक्षा बचाओ और कीड़े नहीं, क्रांतिकारी हैं हम जैसे स्लोगन शामिल रहे। कई पोस्ट में इस्तीफे का मौसम शुरू हो गया है।

अभी खतरे के निशान से दूर यमुना, 30 जुलाई तक पहाड़ों पर बारिश से जलस्तर बढ़ने का अनुमान

मध्य स्वर्णिम, नई दिल्ली।

यमुना का जलस्तर 202.30 मीटर है, जो खतरे के निशान से दूर है। हथिनीकुंड बैराज से 26 जुलाई को 11,300 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 28-29 जुलाई को पहाड़ों में बारिश से जलस्तर बढ़ने की संभावना है। मानसून आने के बाद से अब तक यमुना में जलस्तर अभी खतरे के निशान से दूर होने के चलते यमुना किनारे रहने वालों दिल्लीवासियों में चैन और सुकून हैं। रविवार को भी यमुना का अधिकतम जलस्तर 202.30 तक चल रहा है। हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से रविवार सुबह नौ बजे 11300 क्यूसेक पानी अधिकतम छोड़ा गया है। आने वाले सप्ताह में मौसम विभाग के पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक बारिश की चेतावनी है। ऐसे में बारिश से यमुना जलस्तर में कुछ बढ़ोतरी की संभावना है। दिल्ली में ओल्ड रेलवे पुल पर यमुना का खतरे का निशान 205.33 है। वहीं, चेतावनी स्तर पर 204.50 है। 10 जुलाई 2026 को हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से 50 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। इस दौरान दिल्ली में यमुना का जलस्तर चेतावनी स्तर के नजदीक पहुंच गया था। हालांकि, इसके बाद से पहाड़ों में बारिश की कमी के चलते हथिनीकुंड बैराज से यमुना में पानी कम छोड़ा गया। इस सप्ताह 23 जुलाई को दो बजे हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से यमुना में अधिकतम 16 हजार क्यूसेक तक पानी छोड़ा गया। बाढ़ नियंत्रण विभाग की ओर से बताया गया कि पिछले एक सप्ताह में यह मात्रा सबसे अधिक रही। रविवार सुबह नौ बजे हथिनीकुंड बैराज से लगभग 11 हजार 300 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं, शाम तक यह लगभग पांच हजार से छह हजार क्यूसेक तक यमुना में पानी छोड़ा गया। इस दौरान यमुना का जलस्तर लगभग 202 के आसपास बना हुआ है। दूसरी तरफ, मौसम विभाग के अनुसार 28 और 29 जुलाई को पहाड़ों पर अधिक बारिश की संभावना है। ऐसे में हथिनीकुंड बैराज से अधिक पानी छोड़े जाने और यमुना के जलस्तर में भी बढ़ोतरी की संभावना है।

पेपर लीक के बाद अब ई20 की बारी! केजरीवाल बोले- एकजुट होकर उठानी होगी आवाज

मध्य स्वर्णिम, नई दिल्ली।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब ई20 पेट्रोल का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं ने एकजुट होकर आवाज उठाई तो सरकार को झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। इसी तरह ई20 के मुद्दे पर भी लोगों को एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी होगी। केजरीवाल ने शनिवार को %नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट ई20% आयोजित करने का ऐलान किया। उन्होंने लोगों से इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की। उनके मुताबिक, कार्यक्रम में ई20 से प्रभावित लोगों, विशेषज्ञों और इस मुद्दे से जुड़े अन्य लोगों को एक मंच पर लाया जाएगा, जहां वे अपनी बात रख सकेंगे। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि जिस तरह पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार ने कदम उठाया है, उसी तरह ई20 के मामले का भी समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि लोग ई20 को लेकर परेशान हैं और उनकी गाड़ियों में खराबी आने की शिकायतें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि ई20 के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सभी लोगों को एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है। इस कार्यक्रम के जरिए लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और सरकार के सामने उनकी चिंताओं को रखा जाएगा। केजरीवाल ने बताया कि नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट ई20 कार्यक्रम शनिवार को दोपहर 12 बजे शुरू होगा। दिल्ली और आसपास के शहरों से आने वाले लोगों से उन्होंने सुबह 11:30 बजे तक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचने की अपील की है।

प्रधानमंत्री से ई20 मामले का समाधान करने की अपील

■ उन्होंने कहा कि जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते, वे ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। केजरीवाल ने उम्मीद जताई कि बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन भी कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। केजरीवाल के मुताबिक, टाउनहॉल में ई20 के मुद्दे में रुचि रखने वाले विशेषज्ञों और इससे कथित तौर पर प्रभावित लोगों को बोलने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं और अनुभवों को सामने रखने के साथ-साथ ई20 नीति को लेकर आगे की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी।

जब छात्रों की आवाज़ पर बैरिकेड खड़े कर दिए जाएं

लोकतंत्र की पहचान केवल इस बात से नहीं होती कि चुनाव कितनी नियमितता से होते हैं, बल्कि इस बात से भी होती है कि सरकार अपने नागरिकों की असहमति को किस दृष्टि से देखती है। जब युवा अपने भविष्य को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, तब सरकार के सामने दो रास्ते होते हैं—संवाद का या दमन का। इतिहास बताता है कि संवाद लोकतंत्र को मजबूत करता है, जबकि दमन केवल असंतोष को स्थगित करता है; समाप्त नहीं करता। नीट पेपर लीक प्रकरण ने पूरे देश में करोड़ों छात्रों और अभिभावकों के मन में परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। बिहार, जहाँ प्रतियोगी परीक्षाएँ लाखों युवाओं के जीवन का सबसे बड़ा सहारा हैं, वहाँ इस मुद्दे ने स्वाभाविक रूप से व्यापक राजनीतिक और सामाजिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग को लेकर छात्र संगठन आइसा ने बिहार बंद का आह्वान किया। इस बंद को राष्ट्रीय जनता दल, विकासशील इंसान पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) सहित कई दलों का समर्थन मिला।

बंद के आह्वान के साथ ही पटना से लेकर राज्य के विभिन्न जिलों तक प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखाई दिया। राजधानी के वीआईपी क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में बदल दिया गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। वाटर कैनन तैयार रखे गए। कई स्थानों पर छात्र नेताओं के घरों पर छापेमारी की खबरें सामने आईं। समस्तीपुर, सीवान, गया और अन्य जिलों में प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम किए, टायर जलाए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए।

इन घटनाओं को केवल कानून-व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखना पर्याप्त नहीं होगा। इनके पीछे वह गहरी बेचैनी है जो वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं, भर्ती प्रक्रियाओं और रोजगार के संकट से जूझ रहे युवाओं के भीतर जमा होती रही है।

पेपर लीक किसी प्रश्नपत्र का अवैध प्रसार भर नहीं है। यह समान अवसर के संवैधानिक सिद्धांत पर सीधा आघात है। जो छात्र वर्षों तक कठिन परिश्रम करते हैं, सीमित संसाधनों में तैयारी करते हैं और अपने परिवारों की उम्मीदों का भार उठाते हैं, उनके लिए प्रश्नपत्र लीक होना केवल परीक्षा का रद्द होना नहीं, बल्कि भविष्य की अनिश्चितता का प्रतीक बन जाता है। बिहार इस पीड़ा को सबसे गहराई से समझता है। राज्य के हजारों गाँवों में ऐसे परिवार हैं जो अपनी सीमित आय का बड़ा हिस्सा बच्चों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर खर्च करते हैं। कोई खेत गिरवी रखता है, कोई गहने बेचता है, कोई कर्ज लेकर बेटे-बेटी को कोचिंग भेजता है। जब परीक्षा रद्द होती है या उसकी निष्पक्षता पर प्रश्न उठते हैं, तब उसका आघात केवल अभ्यर्थी तक सीमित नहीं रहता; पूरा परिवार टूटता है।

इसी कारण छात्र आंदोलन को केवल राजनीतिक गतिविधि मान लेना वास्तविक समस्या से आँखें मूँद लेना होगा। यह भी सही है कि राज्य की जिम्मेदारी कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। यदि कहीं हिंसा होती है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचता है या न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन होता है, तो पुलिस को कार्रवाई का अधिकार है। लेकिन लोकतांत्रिक शासन की कसौटी यह है कि वह बल प्रयोग को अंतिम विकल्प बनाए, पहला नहीं। शांतिपूर्ण विरोध और हिंसक उपद्रव के बीच स्पष्ट अंतर किया जाना चाहिए।

भारतीय संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने का अधिकार देता है। ये अधिकार निरपेक्ष नहीं हैं, परंतु इन पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध भी संविधान की कसौटी पर खरे उतरने चाहिए। लोकतंत्र का उद्देश्य असहमति को समाप्त करना नहीं, बल्कि उसे संवैधानिक ढंग से अभिव्यक्ति का अवसर देना है।

दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और उसके विरोध में बिहार बंद की पृष्ठभूमि में यह प्रश्न और महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या सरकार ने संवाद के सभी रास्ते अपनाने के बाद ही कठोर प्रशासनिक उपाय किए? यदि संवाद की संभावना मौजूद थी, तो उसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। बिहार का राजनीतिक इतिहास छात्र आंदोलनों से गहराई से जुड़ा है। 1974 का संपूर्ण क्रांति आंदोलन इसी धरती से उठी छात्र चेतना का परिणाम था। उस आंदोलन ने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। उस समय भी सत्ता ने आंदोलन को कानून-व्यवस्था का प्रश्न बताया था, लेकिन इतिहास ने उसे लोकतांत्रिक जागरण के रूप में स्वीकार किया।

आज परिस्थितियाँ भिन्न हैं, लेकिन मूल प्रश्न वही है—क्या युवा अपनी बात कह सकते हैं? और यदि कहते हैं, तो क्या उन्हें सुना जाएगा?

यह भी सच है कि किसी भी जनांदोलन में राजनीतिक दल सक्रिय हो जाते हैं। बिहार बंद को कई विपक्षी दलों का समर्थन मिला। सरकार इसे राजनीतिक रंग देने का प्रयास बता सकती है। लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदलता कि नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता का संकट वास्तविक है। यदि मूल समस्या मौजूद है, तो उसका समाधान राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से नहीं होगा।

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष युवाओं का मनोविज्ञान है। बेरोजगारी, भर्ती में विलंब, बार-बार परीक्षा रद्द होना और चयन प्रक्रियाओं पर संदेह—इन सबने युवाओं में गहरी निराशा पैदा की है। यदि इस निराशा का उत्तर केवल पुलिस बल से दिया जाएगा, तो लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विश्वास कमजोर पड़ सकता है। सरकार के सामने चुनौती दोहरी है। एक ओर उसे कानून-व्यवस्था बनाए रखनी है, दूसरी ओर युवाओं का विश्वास भी लौटाना है।

मीराबाई चानू ने रचा इतिहास, खेल महाशक्ति बनने की दस्तक

कुमार कृष्णन

खेलों के इतिहास में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो केवल पदकों की संख्या से नहीं, बल्कि अपने सांकेतिक महत्व से याद रखे जाते हैं। वे किसी खिलाड़ी की व्यक्तिगत उपलब्धि से आगे बढ़कर पूरे राष्ट्र के आत्मविश्वास, उसकी सामूहिक आकांक्षाओं और भविष्य की दिशा का संकेत बन जाते हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू का स्वर्ण पदक ऐसा ही एक क्षण है। महिलाओं की 48 किलोग्राम स्पर्धा में 190 किलोग्राम भार उठाकर उन्होंने केवल स्वर्ण पदक ही नहीं जीता, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि भारतीय खेल अब प्रतिभा के भरोसे नहीं, बल्कि निरंतरता, वैज्ञानिक तैयारी और अदम्य आत्मविश्वास के नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं। ग्लासगो में भारत के अभियान की शुरुआत जिस अंदाज़ में हुई, उसने यह संदेश दिया कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारत अब केवल पदक तालिका में सम्मानजनक स्थान पाने का लक्ष्य लेकर नहीं उतरता, बल्कि अनेक स्पर्धाओं में प्रभुत्व स्थापित करने की क्षमता विकसित कर चुका है।

भारोत्तोलन में पहले ही दिन स्वर्ण और दो रजत पदक इस विश्वास को और मजबूत करते हैं। मीराबाई चानू ने स्नैच में 85 किलोग्राम तथा क्लीन एंड जर्क में 105 किलोग्राम भार उठाकर कुल 190 किलोग्राम का स्कोर बनाया। यह केवल स्वर्ण जीतने के लिए पर्याप्त नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से पूरे 22 किलोग्राम अधिक वजन उठाकर अपनी श्रेष्ठता निर्विवाद रूप से स्थापित कर दी। खेलों की दुनिया में ऐसी जीतें बहुत कम देखने को मिलती हैं, जहां विजेता और दूसरे स्थान के बीच इतना बड़ा अंतर हो। यह अंतर केवल ताकत का नहीं, बल्कि तैयारी, तकनीक और मानसिक दृढ़ता का भी होता है।

इस स्वर्ण के साथ मीराबाई ने राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीतकर एक नई मिसाल कायम की। किसी भी खिलाड़ी के लिए एक बार चैंपियन बनना कठिन होता है, लेकिन वर्षों तक अपने प्रदर्शन को उसी स्तर पर बनाए रखना उससे कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। खेल इतिहास बताता है कि महान खिलाड़ी वही कहलाते हैं जो समय के साथ स्वयं को बार-बार साबित करते हैं। मीराबाई अब उसी श्रेणी में खड़ी दिखाई देती हैं। उनकी यात्रा भारतीय खेलों की सबसे प्रेरक यात्राओं में से एक है। मणिपुर के छोटे से गांव नोंगपोक काकचिंग में जन्मी यह बेटी बचपन में सिर पर लकड़ियों के भारी गट्ठर उठाती थी। शायद उसी कठिन जीवन ने उनके कंधों को वह मजबूती दी, जिसने आगे चलकर विश्व मंच पर भारत का भार उठाने की क्षमता पैदा की। आर्थिक कठिनाइयों, सीमित संसाधनों, चोटों और असफलताओं के बावजूद उन्होंने कभी अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया। टोक्यो ओलंपिक का रजत पदक हो या विश्व चैंपियनशिप में सफलता—हर उपलब्धि के पीछे वर्षों का मौन संघर्ष छिपा हुआ है।

मीराबाई की जीत का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि भारतीय महिला खेल आंदोलन की भी बड़ी सफलता है। कभी खेलों में महिलाओं की भागीदारी अपवाद मानी जाती थी। आज पी. वी. सिंधु, निकहत ज़रीन, साक्षी मलिक, लवलीना बोरगोहैन और मीराबाई चानू जैसी खिलाड़ी भारतीय खेलों की पहचान बन चुकी हैं। यह परिवर्तन केवल खेल के मैदान तक सीमित नहीं है; यह भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति बदलती सोच और बढ़ते आत्मविश्वास का भी प्रमाण है।

ग्लासगो में भारत की सफलता केवल मीराबाई तक सीमित नहीं रही। पुरुषों की 60 किलोग्राम स्पर्धा में चनामबम ऋषिकांत सिंह ने रजत पदक जीतकर भारतीय अभियान को नई ऊर्जा दी। उन्होंने कुल 264 किलोग्राम वजन उठाया और स्नैच में 121 किलोग्राम का भार उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों का नया रिकॉर्ड स्थापित किया। यह उपलब्धि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रिकॉर्ड केवल जीत का प्रमाण नहीं होते, वे यह बताते हैं कि खिलाड़ी प्रतियोगिता के मानकों को बदलने की क्षमता रखता है।

ऋषिकांत सिंह का प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि भारतीय भारोत्तोलन में प्रतिभाओं की नई पीढ़ी तैयार हो चुकी है। अब भारत की सफलता किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं रही। यह एक स्वस्थ खेल संस्कृति की पहचान है, जहां लगातार नए खिलाड़ी सामने आते हैं और अनुभवी खिलाड़ियों की विरासत को आगे बढ़ाते हैं। इसी क्रम में राजा मुथुपंडी ने पुरुषों की 65 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक जीतकर भारत के खाते में एक और सफलता जोड़ दी। तीन पदकों ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारोत्तोलन अब भारत के लिए सबसे भरोसेमंद खेलों में शामिल हो चुका है। कभी यह खेल डोपिंग विवादों और प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण चर्चा में रहता था। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ पर कई बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिक प्रशिक्षण, पोषण, खेल विज्ञान, बेहतर निगरानी और खिलाड़ियों के अनुशासन ने इस खेल की तस्वीर बदल दी है। ग्लासगो की सफलता उसी परिवर्तन की कहानी है। भारतीय दल के लिए यह भी उत्साहजनक रहा कि पैरा पावरलिफ्टिंग में झंडू कुमार ने कांस्य पदक जीतकर यह साबित किया कि भारत का पैरा खेल आंदोलन भी निरंतर मजबूत हो रहा है। यह उपलब्धि बताती है कि खेल केवल शारीरिक क्षमता का नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति और अदम्य संकल्प का भी नाम है।

इन सफलताओं का एक महत्वपूर्ण सामाजिक आयाम भी है। मीराबाई चानू और ऋषिकांत सिंह दोनों मणिपुर से आते हैं। पूर्वोत्तर भारत लंबे समय से देश को उत्कृष्ट खिलाड़ी देता रहा है। मुक्केबाजी में मैरी कॉम, भारोत्तोलन में मीराबाई और अब ऋषिकांत जैसे खिलाड़ी बताते हैं कि यह क्षेत्र भारतीय खेलों की नई ऊर्जा का स्रोत है। दुर्भाग्य से यह क्षेत्र लंबे समय तक विकास और खेल सुविधाओं के मामले में उपेक्षित रहा। फिर भी वहां की प्रतिभाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि अवसर मिलने पर वे विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन कर सकती हैं। यह सरकारों के लिए भी संदेश है कि खेल अवसंरचना का विस्तार केवल महानगरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। भारतीय खेलों का परिदृश्य पिछले एक दशक में तेजी से बदला है। कभी क्रिकेट ही राष्ट्रीय खेल चेतना का पर्याय बन गया था, लेकिन अब बैडमिंटन, मुक्केबाजी, कुश्ती, निशानेबाजी, एथलेटिक्स, हॉकी और भारोत्तोलन जैसे खेल भी व्यापक जनसमर्थन प्राप्त कर रहे हैं। यह परिवर्तन स्वस्थ लोकतांत्रिक खेल संस्कृति का संकेत है। जब किसी देश में अनेक खेलों के खिलाड़ी राष्ट्रीय नायक बनने लगते हैं।

आत्म विकास का अपूर्व अवसर चातुर्मास

वैदिक और बौद्ध परंपराओं में भी इन चार महीनों को साधना तप और आत्मानुशासन का श्रेष्ठ समय माना गया। देवशयन का प्रतीक भी इसी भावना को व्यक्त करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान वास्तव में सो जाते हैं बल्कि यह संकेत है कि मनुष्य अपनी बाहरी प्रवृत्तियों को सीमित करे और अंतर्मुखी बने। जब संसार की चकाचौंध थोड़ी मंद होती है तभी आत्मा का प्रकाश अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। भगवान महावीर और जयन्ती श्राविका के संवाद में भी यही गूढ़ संदेश मिलता है। जब जयन्ती ने पूछा कि सोना अच्छा है या जागना तो भगवान ने उत्तर दिया कि हिंसा और पाप में लगे लोगों का सोना अच्छा है।

कांतिलाल मांडोत

भारतीय संस्कृति में समय को केवल दिनों और महीनों की गणना नहीं माना गया बल्कि जीवन को दिशा देने वाली शक्ति के रूप में देखा गया है। प्रत्येक कार्य का अपना एक उपयुक्त समय होता है। जब कार्य समय के अनुरूप किया जाता है तब उसका परिणाम भी श्रेष्ठ होता है। यही कारण है कि हमारे ऋषियों और आचार्यों ने जीवन को ऋतु और काल के साथ जोड़कर साधना की परंपराएं विकसित कीं। चातुर्मास ऐसी ही एक अनुपम परंपरा है जो मनुष्य को बाहरी दौड़ से हटाकर अपने भीतर लौटने का अवसर देती है। यह केवल चार महीनों का धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आत्मविकास आत्मसंयम और जीवन के पुनर्निर्माण का काल है।

योगवशिष्ठ में कहा गया है कि महापुरुष कभी भी समय की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। वे जानते हैं कि प्रत्येक कार्य की सफलता में काल का अत्यंत महत्त्व है। किसान यदि समय पर बीज न बोए तो उपज नहीं मिलती। इसी प्रकार मनुष्य यदि उचित समय पर आत्मचिंतन और साधना न करे तो जीवन की उर्वरता भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। चातुर्मास इसी उचित समय का नाम है। यदि इस सत्य को एक अलग दृष्टांत से समझें तो कल्पना कीजिए कि कोई कुशल मूर्तिकार वर्षों तक एक विशाल प्रतिमा गढ़ता है। वह हर दिन छैनी नहीं चलाता। कुछ समय ऐसा भी आता है जब वह केवल दूर खड़ा होकर प्रतिमा को देखता है। वह यह परखता है कि अगली चोट कहां करनी है ताकि पूरी आकृति बिगड़े नहीं। यदि वह बिना रुके केवल प्रहार करता रहे तो उत्कृष्ट मूर्ति भी नष्ट हो सकती है। मनुष्य का जीवन भी ऐसी ही एक मूर्ति है। चातुर्मास वह समय है जब जीवन पर लगातार प्रहार करने के बजाय रुककर स्वयं को देखने की आवश्यकता होती है। यही ठहराव आगे की श्रेष्ठ यात्रा का आधार बनता है। वर्षा ऋतु में प्रकृति का पूरा स्वरूप बदल जाता है।

धरती को नया जीवन मिलता है। सूखे बीज अंकुरित हो जाते हैं। वातावरण में नमी बढ़ जाती है और असंख्य सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है। जैन परंपरा ने इस प्राकृतिक परिवर्तन को केवल मौसम का बदलाव नहीं माना बल्कि करुणा और अहिंसा के अभ्यास का अवसर बनाया। इसी कारण भगवान महावीर के शासन में साधु साध्वियों के लिए वर्षावास का विधान किया गया ताकि वे अनावश्यक विहार से बचें और सूक्ष्म जीवों की हिंसा न्यूनतम हो। चातुर्मास का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन की गति जितनी आवश्यक है उतना ही आवश्यक है उसका विराम। आज का मनुष्य निरंतर भाग रहा है। उसके पास उपलब्धियां हैं लेकिन आत्मसंवाद का समय नहीं है। चातुर्मास इस भागदौड़ के बीच यह स्मरण कराता है कि बाहरी यात्रा तभी सार्थक है जब भीतर का पथ भी प्रकाशित हो।

भारतीय परंपरा में चातुर्मास केवल जैन धर्म तक सीमित नहीं रहा। वैदिक और बौद्ध परंपराओं में भी इन चार महीनों को साधना तप और आत्मानुशासन का श्रेष्ठ समय माना गया। देवशयन का प्रतीक भी इसी भावना को व्यक्त करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान वास्तव में सो जाते हैं बल्कि यह संकेत है कि मनुष्य अपनी बाहरी प्रवृत्तियों को सीमित करे और अंतर्मुखी बने। जब संसार की चकाचौंध थोड़ी मंद होती है तभी आत्मा का प्रकाश अधिक स्पष्ट दिखाई देता है।

भगवान महावीर और जयन्ती श्राविका के संवाद में भी यही गूढ़ संदेश मिलता है। जब जयन्ती ने पूछा कि सोना अच्छा है या जागना तो भगवान ने उत्तर दिया कि हिंसा और पाप में लगे लोगों का सोना अच्छा है और दया संयम तथा सदाचार में लगे लोगों का जागना श्रेष्ठ है। यह उत्तर केवल शब्दों का कौशल नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। चातुर्मास हमें यही सिखाता है कि हमारे भीतर का क्रोध लोभ कपट और प्रमाद सो जाए तथा करुणा विवेक और संयम जाग उठें।

इन चार महीनों का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष पर्यावरण और स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। वर्षा ऋतु में जल दूषित होता है। संक्रमण फैलते हैं। भोजन जल्दी खराब होता है और शरीर की पाचन शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। इसलिए संयमित भोजन उपवास एकासन आयंबिल और रात्रि भोजन का त्याग केवल धार्मिक नियम नहीं बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी हैं। हमारे प्राचीन आचार्यों ने धर्म और आरोग्य दोनों को साथ लेकर नियम बनाए थे। यही उनकी दूरदृष्टि थी। चातुर्मास का एक और अत्यंत महत्त्वपूर्ण पक्ष है व्रत और नियम। आज अनेक लोग नियम लेने से इसलिए डरते हैं कि कहीं उसका पालन न कर सके तो दोष लगेगा। जबकि वास्तव में नियम मनुष्य की संकल्पशक्ति को मजबूत बनाता है। बिना नियम के जीवन इच्छाओं के प्रवाह में बहता रहता है। नियम उस प्रवाह पर बांध का कार्य करता है। जब मन किसी विषय से त्यागपूर्वक अलग होता है तभी वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव होता है।

स्वस्थ भोजन हर नागरिक का अधिकार

स्वाद के लिए लोग इन्हें पसंद तो करते हैं लेकिन धीरे-धीरे यही भोजन मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म देता है। विशेष रूप से युवाओं और बच्चों में यह प्रवृत्ति चिंता का विषय बनती जा रही है। दरअसल, स्वस्थ रहने के लिए महंगे भोजन की नहीं बल्कि संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। दालें, मौसमी सब्जियां, मोटे अनाज, दूध, दही, अंकुरित अनाज और स्थानीय फल अपेक्षाकृत कम खर्च में भी अच्छा पोषण दे सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि लोग खानपान के प्रति जागरूक हों और जितनी क्षमता हो, उसके अनुसार पौष्टिक भोजन को प्राथमिकता दें।

कांतिलाल मांडोत

भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जिस समाज के लोगों को संतुलित और पौष्टिक भोजन नहीं मिलता वहां बीमारियां बढ़ती हैं, बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है और देश की कार्यक्षमता भी कमजोर पड़ती है। संयुक्त राष्ट्र की स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड (एसओएफआई) 2026 रिपोर्ट ने एक गंभीर चिंता सामने रखी है कि भारत में लगभग 52 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी पहुंच आज भी नियमित रूप से पौष्टिक और संतुलित आहार तक नहीं है। यह स्थिति तब है जब देश ने पिछले वर्षों में कुपोषण कम करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। इसका अर्थ यह है कि समस्या केवल भोजन की उपलब्धता की नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण भोजन की भी है।

आज बाजार में फल, सब्जियां, दूध, दालें, अंडे, मेवे और अन्य प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। सीमित आय वाले परिवारों के लिए रोजाना संतुलित भोजन जुटाना आसान नहीं रह गया है। कई परिवार पेट भरने के लिए सस्ता भोजन तो खरीद लेते हैं लेकिन उसमें आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है। इसका असर सबसे पहले बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों पर दिखाई देता है। शरीर को पर्याप्त प्रोटीन, विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्व नहीं मिलते तो प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है और कई बीमारियां घर कर लेती हैं। यह सच है कि पहले की तुलना में देश में कुपोषण की स्थिति में काफी सुधार आया है। सरकारी योजनाओं, आंगनबाड़ी सेवाओं, मध्याह्न भोजन योजना और जनजागरूकता के कारण लाखों परिवारों तक बेहतर पोषण पहुंचा है। लेकिन चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई है। आज भी अनेक लोग आर्थिक मजबूरी के कारण पौष्टिक भोजन से दूर हैं। यही कारण है कि एक ओर कुपोषण की समस्या बनी हुई है तो दूसरी ओर मोटापा और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियां भी तेजी से बढ़ रही हैं।

इसका कारण यह है कि लोग सस्ता और तला-भुना या अत्यधिक प्रसंस्कृत भोजन अधिक खाने लगे हैं, जिसमें स्वाद तो होता है लेकिन पोषण कम होता है।

आज का सबसे बड़ा संकट केवल महंगाई नहीं बल्कि भोजन की गुणवत्ता भी है। बाजार में मिलावटी खाद्य पदार्थों की भरमार चिंता बढ़ाने वाली है। दूध में मिलावट, मसालों में नकली रंग, मिठाइयों में घटिया सामग्री, नकली घी, मिलावटी तेल, रसायनों से पकाए गए फल और सब्जियां तथा खराब गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ लोगों के स्वास्थ्य के साथ खुला खिलवाड़ कर रहे हैं। उपभोक्ता पैसे खर्च करके भी शुद्ध भोजन नहीं खरीद पा रहा है। यह स्थिति किसी भी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं कही जा सकती।

बाहर का भोजन भी लोगों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। भागदौड़ भरी जिंदगी में फास्ट फूड और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों का चलन तेजी से बढ़ा है। इन खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक, चीनी और वसा होती है। स्वाद के लिए लोग इन्हें पसंद तो करते हैं लेकिन धीरे-धीरे यही भोजन मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म देता है। विशेष रूप से युवाओं और बच्चों में यह प्रवृत्ति चिंता का विषय बनती जा रही है। दरअसल, स्वस्थ रहने के लिए महंगे भोजन की नहीं बल्कि संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। दालें, मौसमी सब्जियां, मोटे अनाज, दूध, दही, अंकुरित अनाज और स्थानीय फल अपेक्षाकृत कम खर्च में भी अच्छा पोषण दे सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि लोग खानपान के प्रति जागरूक हों और जितनी क्षमता हो, उसके अनुसार पौष्टिक भोजन को प्राथमिकता दें। कम मात्रा में सही भोजन लेना, अधिक मात्रा में अस्वस्थ भोजन खाने से कहीं बेहतर है।

सरकार की जिम्मेदारी है कि गरीब और मध्यम वर्ग तक पौष्टिक भोजन सुलभ कीमत पर पहुंचे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और मजबूत बनाने, पोषण योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने, खाद्य पदार्थों की कीमतों पर नियंत्रण रखने और किसानों को उचित समर्थन देने की आवश्यकता है। यदि उत्पादन बढ़ेगा और आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी तो कीमतों पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। लेकिन केवल सरकार से अपेक्षा करना पर्याप्त नहीं है। समाज, उद्योग और बाजार की भी बड़ी जिम्मेदारी है। खाद्य व्यापार से जुड़े लोगों को यह समझना होगा कि भोजन केवल व्यापार की वस्तु नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है। कुछ अतिरिक्त मुनाफे के लिए मिलावट करना, नकली सामग्री बेचना या घटिया गुणवत्ता का सामान बाजार में उतारना केवल कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि मानवता के साथ विश्वासघात है। जिस भोजन से लोगों का शरीर बनता है।

धरती की चेतावनी को सुनिए, प्रकृति का धैर्य अब दे रहा है जवाब

योगेश कुमार गोयल

पूरी दुनिया में मौसम के तेजी से बिगड़ते मिजाज के कारण विभिन्न देशों में प्रकृति की मार अब स्पष्ट नजर आने लगी है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ का ही परिणाम है कि अब हर साल देश के कई हिस्से भारी बारिश के कारण बाढ़ की वजह से त्राहि-त्राहि करते नजर आते हैं जबकि कई हिस्से मानसून के दौरान भी पर्याप्त बारिश के लिए तरसते रह जाते हैं। इस वर्ष भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। दुनिया के कई ठंडे इलाके अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण तपने लगे हैं तो कई सूखे इलाके बाढ़ से त्रस्त हैं, जंगल झुलस रहे हैं। बिगड़ते पर्यावरणीय संतुलन और मौसम चक्र में आते बदलाव के कारण पेड़-पौधों की अनेक प्रजातियों के अलावा जीव-जंतुओं की कई प्रजातियों के अस्तित्व पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं।

पर्यावरण के तेजी से बदलते इस दौर में वैश्विक स्तर पर लोगों का ध्यान इन समस्याओं की ओर आकृष्ट करने के लिए ही प्रतिवर्ष 28 जुलाई को 'विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस' मनाया जाता है, जिसके माध्यम से वातावरण में हो रहे व्यापक बदलावों के चलते लगातार विलुप्ति के कगार पर पहुंच रही जीव जंतुओं और वनस्पतियों की अनेक प्रजातियों की रक्षा का संकल्प लिया जाता है। विश्वभर में आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण के चलते प्रकृति के साथ बड़े पैमाने पर जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके मद्देनजर आमजन को जागरूक करने के लिहाज से आज के समय में प्रकृति संरक्षण दिवस की महत्ता बढ़ गई है। 2020 में कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौर में पूरी दुनिया ने पहली बार प्रकृति को खुलकर मुस्कराते देखा था क्योंकि तब औद्योगिक इकाईयां, हवाई व रेल यात्राएं, बस यात्रा तथा निजी वाहनों का आवागमन बंद होने से हर तरह के प्रदूषण का स्तर पूर्ण रूप से नियंत्रित हो गया था।

गंगा, यमुना जैसी जो पवित्र नदियां कई जगहों पर गंदे नालों की भांति बहती दिखाई देती थी, उनमें जल की निर्मल धारा बहने लगी थी। जिन नदियों को साफ करने के लिए पिछले कुछ दशकों में अनेक योजनाएं और समितियां बनी तथा नदियों की स्वच्छता के नाम पर अरबों-खरबों रुपये खर्च हो गए, लॉकडाउन के दौरान वे स्वत: ही स्वच्छ और निर्मल हो गई थी। पहली बार देखा गया था कि किस प्रकार लॉकडाउन के चलते लोगों के घरों में बंद रहने और सभी प्रकार के व्यावसायिक कार्य बंद हो जाने से हवा इतनी शुद्ध हो गई थी कि सैंकड़ों किलोमीटर दूर स्थित पर्वतों की चोटियां भी स्पष्ट दिखाई दी थी। जिन नन्हीं चिड़ियों की चहचहाहट को हमारे कान तरस गए थे, ब्रह्म मुहूर्त में उनकी मधुर आवाज फिर से सुनाई देनी लगी थी। प्रकृति के उस साफ-सुथरे स्वरूप को देखकर हर कोई खुश था। दरअसल प्रकृति को स्वयं अपनी मरम्मत करने और खुद को सजाने-संवारने का सुअवसर मिला था लेकिन इंसानी गतिविधियां पुन: शुरू होते ही प्रकृति के साथ निर्मम खिलवाड़ का वही दौर पुन: शुरू हो गया, जिसका परिणाम इस समय दुनिया के तमाम देश भुगत रहे हैं। लॉकडाउन के दौर ने पूरी दुनिया को यह समझने का बेहतरीन अवसर दिया था कि इंसानी गतिविधियों के कारण ही प्रकृति का जिस बड़े पैमाने पर दोहन किया जाता रहा है, उसी के कारण स्वर्ग से भी सुंदर हमारी धरती कराहती रही है। प्रकृति मनुष्य को ऐसा न करने के लिए बार-बार किसी न किसी बड़ी आपदा के रूप में चेतावनियां भी देती रही है लेकिन उन चेतावनियों को सदा दरकिनार किया जाता रहा है। प्रकृति के साथ मानवीय छेड़छाड़ का ही नतीजा रहा है कि बीते कुछ वर्षों में मौसम चक्र में बदलाव स्पष्ट दिखाई दिया है।

वर्ष दर वर्ष अब जिस प्रकार मौसम के बिगड़ते मिजाज के चलते समय-समय पर तबाही देखने को मिल रही है, ऐसे में हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि मौसम चक्र के बदलाव के कारण प्रकृति संतुलन पर जो विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, उसकी अनदेखी के कितने भयावह परिणाम होंगे। प्रकृति बार-बार मौसम चक्र में बदलाव के संकेत, चेतावनी तथा संभलने का अवसर देती रही है लेकिन हम आदतन किसी बड़े खतरे के सामने आने तक ऐसे संकेतों या चेतावनियों को नजरअंदाज करते रहे हैं, जिसका नतीजा अक्सर भारी तबाही के रूप में सामने आता रहा है। पिछले तीन दशकों से पर्यावरण प्रदूषण के कारण जिस प्रकार मौसम चक्र तीव्र गति से बदल रहा है और प्राकृतिक आपदाओं का आकस्मिक सिलसिला तेज हुआ है, उसके बावजूद यदि हम नहीं संभलना चाहते तो इसमें भला प्रकृति का क्या दोष? प्रकृति के साथ हम बड़े पैमाने पर जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसी का नतीजा है कि पिछले कुछ समय में भयानक तूफानों, बाढ़, सूखा, भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला तेजी से बढ़ा है। अपनी पुस्तक 'प्रदूषण मुक्त सांसें' में मैंने विस्तार से यह बताया है कि किस प्रकार पर्यावरण का संतुलन डगमगाने के चलते लोग अब तरह-तरह की भयानक बीमारियों के जाल में फंस रहे हैं। हमारे जो पर्वतीय स्थान कुछ सालों पहले तक शांत और स्वच्छ वातावरण के कारण हर किसी को अपनी ओर आकर्षित किया करते थे, आज वहां भी प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है और ठंडे इलाकों के रूप में विख्यात पहाड़ भी तपने लगने हैं, वहां भी जल संकट गहराने लगा है। दरअसल पर्वतीय क्षेत्रों में यातायात के साधनों से बढ़ते प्रदूषण, बड़े-बड़े उद्योग स्थापित करने और राजमार्ग बनाने के नाम पर बड़े पैमाने पर वनों के दोहन, सुरंगें बनाने के लिए बेदर्दी से पहाड़ों का सीना चीरे जाने का ही दुष्परिणाम है कि हमारे इन खूबसूरत पहाड़ों की ठंडक अब लगातार कम हो रही है।

पहाड़ों में बढ़ती इसी गर्माहट के चलते हमें अक्सर घने वनों में भयानक आग लगने की खबरें भी सुनने को मिलती रहती हैं। पहाड़ों की इसी गर्माहट का सीधा असर निचले मैदानी इलाकों पर पड़ता है, जहां का पारा अब वर्ष दर वर्ष बढ़ रहा है। हालांकि प्रकृति बार-बार अपना रौद्र रूप दिखाकर स्पष्ट चेतावनी देती रही है कि यदि उसके साथ अंधाधुंध खिलवाड़ बंद नहीं हुआ तो उसके घातक परिणाम होंगे।

चिंतन-मनन: सुख के स्वभाव में डूबो

लगता है, आदमी दुख का खोजी है। दुख को छोड़ता नहीं, दुख को पकड़ता है। दुख को बचाता है। दुख को संवारता है; तिजोरी में संभालकर रखता है। दुख का बीज हाथ पड़ जाए, हीरे की तरह संभालता है। लाख दुख पाए, पर फेंकने की तैयारी नहीं दिखाता। जो लोग कहते हैं आदमी आनंद का खोजी है, लगता है आदमी की तरफ देखते ही नहीं। आदमी दुखवादी है, अन्यथा संसार इतना दुख में क्यों हो! अगर सभी लोग आनंद खोज रहे हैं, तो संसार में आनंद की थोड़ी झलक होती। कुछ को तो मिलता! और कुछ को मिल जाता तो वे बांटते औरों को भी; तो कुछ झलक उनकी आंखों और उनके प्राणों में भी आती। अगर सभी आनंद की तलाश कर रहे हैं, तो लोग एक-दूसरे को इतना दुख क्यों दे रहे हैं।

और ऐसा नहीं कि पराए ही दुख देते हों, अपने भी दुख देते हैं। अपने ही दुख देते हैं! शत्रु तो दुख देते ही है; हिसाब रखा है, मित्र कितना दुख देते हैं? जिन्हें तुमसे घृणा है, वे तो दुख देंगे, स्वाभाविक; लेकिन जो कहते हैं तुमसे प्रेम है, उन्होंने कितना दुख दिया, उसका हिसाब रखा है? और अगर हर आदमी दुख दे रहा है, तो एक ही बात का सबूत है कि हर आदमी दुख से भरा है। हम वही देते हैं, जिससे हम भरे हैं। वही तो हमसे बहता है जो हमारे भीतर लगा है। हमारे व्यवहार से दूसरों को दुख मिलता है, क्योंकि हमारे भीतर कड़वाहट है। हम लाख कहें हम प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम के नाम पर भी हम दूसरों के जीवन में नरक निर्मित करते हैं। पति-पत्नियों को देखो, मां-बाप को देखो; बेटे-बच्चों को देखो- सब एक-दूसरे की फांसी लगाए हुए है। ऐसा है। क्यों? और सभी कहते हैं कि हम सुख को खोजते हैं। मेरे पास रोज लोग आते हैं, जो कहते हैं- हम सुख चाहते हैं। अगर तुम सुख चाहते हो तो कोई भी बाधा नहीं है; सुख तो लुट रहा है। सुख तो चारों तरफ मौजूद है। ऐसे ही हो तुम, जैसे सामने गंगा बहती हो और किनारे पर खड़े तुम छाती पीटते हो, चिल्लाते हो: प्यासा हूं, मैं जल चाहता हूं!

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक राकेश व्यास द्वारा आरडी प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्रा. लि., बी-48, सेक्टर 8 नोएडा, गौतम बुद्ध नगर उत्तरप्रदेश -201301 से मुद्रित एवं बी-4, गली नं. 2 जगतपुरी कृष्णा नगर ईस्ट, नई दिल्ली-110051 से प्रकाशित। प्रधान संपादक राकेश व्यास, मो : - 09977701999, समूह संपादक सुनील दत्त तिवारी, मो :- 9713 289999, संपादक- ऋषिकान्त सिंह (रजत) परिहार, मो :- 09425002527, स्थानीय संपादक-हितेश जिंदल * मो :-8708040660, ईमेल आईडी : madhyaswarnim@gmail.com समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार होंगे। आरएनआई क्रमांक:- DLHIN/25/A5027

मध्य स्वर्णिम ब्रीफ

उमरेठ के बीजकवाडा में घर में साडी के फंदे पर लटकी मिली महिला

परासिया। उमरेठ के बीजकवाडा में महिला का शव घर में फांसी पर लटका मिला। घटना के दौरान घर सूना था। परिवार के सभी लोग खेत और गाय बैल चराने गए थे। लौटे तो देखा तो कि महिला घर में फांसी के फंदे पर लटकी थी। घटना रविवार को चार बजे के आसपास की है। पुलिस ने सोमवार को बारह बजे पोस्टमार्टम कराया। महिला के पति मुकेश धुर्वे ने बताया कि वह खेती किसानी का काम करता है। उसकी पत्नी रजनी ने रविवार को शराब का नशा कर ली थी। इसके बाद सभी अपने अपने काम पर चले गए। महिला के तीन बच्चे है। वे भी घर पर नहीं थे। सभी वापस लौटे तो महिला फंदे पर लटकी थी। पति ने बताया कि किसी तरह का कोई विवाद लडाई झगडा नहीं था। महिला ने ऐसा क्यों की नहीं पता।

बाईपास में स्कूल से घर लौट रहे छात्र के साथ मारपीट

परासिया। परासिया रावनवाडा बाईपास पर स्कूल से घर लौट रहे ग्यारहवी के छात्र के साथ मारपीट की गई। सोमवार को तीन बजे हुई इस वारदात में छात्र के माथे पर कडे से गंभीर चोट आई। परासिया में उसका पुलिस ने मेडिकल कराया। माथे पर टांके लगाए गए है। घटना को लेकर छात्र ने बताया कि वह स्कूल से लौट रहा था। इसी दौरान आठ दस लडके आए और उससे विवाद करने लगे। इस विवाद में उसके माथे पर कडे से चोट आ गई। उसे टांके लगाए गए है। बालक के परिजन भी सिविल अस्पताल पहुंच गए। डायल 112 से आरक्षक विपिन पांडे और पायलेट अनिल पाल उसे लेकर अस्पताल आए। बालक के पिता ने कहा कि उनके बालक के साथ मारपीट की गई है। इसकी पुलिस में रिपोर्ट कराई गई है।

उमरेठ के पीएम श्री स्कूल मे विद्यार्थियों को मिल साईकिल

परासिया। उमरेठ के पीएमश्री पं विशंभरनाथ पांडे स्कूल में सोमवार को दो बजे साईकिल वितरण समारोह आयोजित किया गया। विद्यालय के दस चयनित छात्राओं को साईकिल बांटी गई। मंडल के भाजपा नेताओं की हस्ते साईकिल वितरण किया गया।,मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री साइकिल वितरण योजना नि :शुल्क साइकिलो का वितरण किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिला महामंत्री एवं जिला पंचायत सदस्य कमलेश उईके , मंडल महामंत्री संदीप सोनी, सरपंच मुकेश सोनी, उपसरपंच विशाल बंदेवार, बूथ अध्यक्ष रोहित साहू, सोशल मीडिया प्रभारी विकास साहू, जयप्रकाश साहू, संदीप वाडिवा, टिंकू साहू ग्राम पंचायत पंच आरती साहू , राधा उईके , कविता पाल ,की ने साईकिल वितरण किया। कार्यक्रम में प्राचार्य अर्चना भारत विद्यालय स्टाफ विद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी, छात्र-छात्राएं और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे, ।

कावड़ यात्रा के लिए कांग्रेस ने बांटे आमंत्रण पत्र

परासिया। ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष कमल राय तीन फरवरी को कांवड यात्रा निकाल रहे हे। इस कांवड यात्रा के लिए नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह ने साथियों के साथ आमंत्रण पत्रों का वितरण किया। ब्लाक समन्वयक बसंत मालवीय , अंजली श्रीवास्तव , प्रतिभा सोनी महिला अध्यक्ष सावित्री वर्मा ज्योति कैथवास ,रीना बाबरिया द्वारा धर जाकर आमंत्रण दिया गया।

आंदोलन नोटिस पर बीएमएस को प्रबंधन ने वार्ता पर बुलाया

प्रबंधन की नहीं थी तैयारी, बीएमएस ने किया बहिष्कार

परासिया। भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ बीएमएस ने प्रबंधन को फार्म एल के तहत स्ट्राईक नाटिस दिया थां इस स्ट्राइक नोटिस पर प्रबंधन ने बीमएएस को वार्ता के लिए बुलाया। वार्ता में प्रबंधन ने कोई तैयारी नहीं की थी। इसके चलते बीएमएस ने वार्ता का बहिष्कार कर दिया।

बैठक में कुछ बिन्दुओं पर चर्चा भी की गई । लेकिन आगे मॉग पत्र पर चर्चा में प्रबंधन द्वारा कोई भी मॉगों पर प्रबंधन की कोई तैयारी नहीं की गई थी और न ही यूनिट के विषयों को लेकर यूनिट में चर्चा की गई थी। जिसके कारण प्रबंधन मॉग-पत्र पर सकारात्मक परिणाम नहीं दे पा रहा था । पदाधिकारियों ने विरोध दर्ज कर बैठक का बहिष्कार किया प्रबंधन को कहा कि जब तक प्रबंधन बैठक में पूर्ण तैयारी से नहीं आता, तब तक हम दिये गये आन्दोलन नोटिस के तहत् आन्दोलन पर जाने हेतु बाध्य होंगे एवं सभी पदाधिकारी नारेबाजी कर बैठक से वापस आ गये ।

बैठक में भा.को. ख.म.संघ,म.प्र.,पेंच-कन्हान के अध्यक्ष मोहित नामदेव, कार्यकारी अध्यक्ष तेजप्रताप शाही, महामंत्री निखीलेश राहा, उपाध्यक्ष अच्छेलाल गुप्ता, आशीष यादव, संयुक्त महामंत्री संजय बावरिया, रामदास सोलंकी, मंत्री दिलीप निषाद, सलीमुद्दीन, देवानंद साहनी, उपमंत्री राजेश पासवान, कार्यालय मंत्री चौखेदास वैष्णव, संगठन मंत्री सुनील पाण्डे, रोहितास वर्मा, कार्यसमिति सदस्य रंजीत सिंह, जेसीसी सदस्य शैलेन्द्र शर्मा, धनकशा माईन शाखाध्यक्ष अंकित एल्डक, नेहरिया माईन शाखाध्यक्ष, माथनी माईन शाखाध्यक्ष अर्जुन यादव, शिवपुरी शाखाध्यक्ष शैलेन्द्र सूर्यवंशी, विष्णुपुरी-2 शाखाध्यक्ष प्रदीप ठाकरे, रावनवाड़ा शाखाध्यक्ष सीमा अहिल्या, बीजीसायडिंग शाखाध्यक्ष नवीन यादव, महादेवपुरी शाखाध्यक्ष भूषण ठाकरे, वर्कशॉप शाखाध्यक्ष

जेल गए कार से बकरियां चुराने के आरोपी

परासिया। न्यूटन पुलिस चौकी के पगारा के गोली परासिया गांव में रविवार को कार से बकरियां चुराने के आरोपियों को न्यायालय ने जेल भेज दिया। सोमवार को साढे चार बजे पुलिस इन्हें जेल दाखिल करने ले गई। तीन आरोपियों को जेल भेजा गया है। गौरतलब है कि गौली परासिया गांव में स्विफ्ट डिजायर कार में बकरियों को कार में भर लिया गया था। ग्रामीणों ने इन्हें देख दिया। इसके बाद पुलिस को शिकायत की गई। न्यूटन चौकी प्रभारी को फोन लगाया गया। तत्काल न्यूटन पुलिस चौकी प्रभारी मौके पर स्टाफ के साथ पहुंचे और बकरियां चोरी करने वाले को न्यूटन चौकी में लाया गया था। तीन आरोपी राकेश डग्गा, आसिफ और करण अर्जुन को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। न्यायालय से सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।

राशन दुकान से बांटा घटिया गुणवत्ता का गेहूं

गरीबों के गेहुं में निकली चूहे की लेंडी, गिट्टी, मिट्टी और कंकड

परासिया। जुलाई माह में परासिया की राशन दुकानों से बेहद खराब गुणवत्ता का गेहूं उपभोक्ताओं का वितरित किया गया है। बांटे गए गेहूं में चूहे की लेंडिया, कंकड, मिट्टी , गिट्टी और पत्थर निकल रहे है। इतनी खराब गुणवत्ता के गेहूं को उपभोक्ताओं को फेंकना पड रहा है। आपूर्ति अधिकारी से कार्रवाई की मांग की गई है।

गौरतलब है कि इन दिनों परासिया की राशन दुकानों का निरीक्षण नहीं होने से दुकानदार मनमर्जी पर उतर आए है। दुकान संचालक और सेल्समैन को जानकारी है कि गेहूं खराब गुणवत्ता का है इसके बाद भी गेहूं के साथ गिट्टी, मिट्टी, पत्थर सब तौल दिए जा रहे है। उपभोक्ता इससे बेहद परेशान है। गरीबों की थाली को लेकर प्रधानमंत्री की सोच को इस तरह पलीता लगाया जा रहा है। वार्ड क्रमांक दस की राशन दुकान से खराब गुणवत्ता का गेहूं बांटे जाने की शिकायत आई। अन्य वार्डों से भी इस तरह की शिकायतें सामने आई है । उपभोक्ताओं ने बताया कि सेल्समैन को इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद भी उसने नहीं माना और खराब गुणवत्ता का गेहूं तौल दिया। कई उपभोक्ताओं को यही गेहूं दिया गया। आपूर्ति अधिकारी से इस मामले में जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है।

बडी बडी गिट्टियां कैसे आई

गेहूं के बोरे से बडी बडी गिट्टियां कैसे आई। यही राशन की बोरियां यही यदि सप्लाई की गई है तो गोदाम में खरीदी के दौरान बडी गडबडी की गई है। इस तरह के मामलों में कार्रवाई की जरूरत है। अधिकारियों, कर्मचारियों की लापरवाही शासन पर भारी पड जाती है ।

शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पाटन को शत-प्रतिशत बोर्ड परीक्षा परिणाम पर जिला प्रशासन ने किया सम्मानित

सीहोर । गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा अंतर्गत आयोजित सांदीपनी उत्सव के सम्मान समारोह में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पाटन (विकासखंड सीहोर) को सत्र 2025-26 में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शत-प्रतिशत परीक्षा परिणाम प्राप्त करने पर जिला प्रशासन द्वारा प्रशस्ति-पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती शाहिना खान के कुशल नेतृत्व, शिक्षकों की सतत मेहनत तथा विद्यार्थियों के अनुशासित प्रयासों से विद्यालय ने यह गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल की। इस सम्मान के लिए विद्यालय परिवार ने जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस उपलब्धि में विद्यालय के समस्त स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनमें श्रीमती आशा दुबे, श्रीमती त्रिशाला जैन, श्रीमती सविता राठौर, श्रीमती नीलिमा टोप्पो, श्री राजेश सिंह सोलंकी, श्री अफजल खान, श्री नवेद हुसैन, श्री दयाशंकर, श्रीमती सपना नामदेव, श्री अशोक कुमार, श्री राहुल मेवाड़ा, श्री रघु दयाल पंचम, श्री सुनील कुमार, श्रीमती पीयूषा देशमुख, श्री राहुल तथा श्रीमती सुहानी शामिल हैं।

मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष ए.पी. सिंह पहुंचे ग्राम चन्देरी व बड़बेली, करंट पीड़ित किसान से की मुलाकात

विद्युत मंडल के अधिकारी जांच में दोषी, कार्रवाई की अनुशंसा ; पीड़ित को न्याय और मुआवजे का दिलाया भरोसा

सीहोर। सीहोर जिले के ग्राम बरबेली में विद्युत मंडल की कथित लापरवाही के कारण 11 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हुए किसान सतीश मेवाड़ा से मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष ए.पी. सिंह ने गांव पहुंचकर मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित किसान, उनके परिजनों और ग्रामीणों से पूरे मामले की जानकारी लेकर निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों पर कार्रवाई करने तथा पीड़ित को न्याय दिलाने का भरोसा दिया।

इस अवसर पर किसान एवं समाजसेवी एमएस मेवाड़ा ने आयोग अध्यक्ष का स्वागत करते हुए उन्हें प्रतीक स्वरूप लकड़ी का हल भेंट किया और पीड़ित किसान की समस्या का शीघ्र समाधान, उचित मुआवजा एवं दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की मांग रखी। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं किसान उपस्थित रहे। करीब एक माह पूर्व खेत में कार्य करते समय 11 केवी की झूलती विद्युत लाइन की चपेट में आने से किसान सतीश मेवाड़ा गंभीर रूप से झुलस गए थे। हादसे में उनका एक हाथ काटना पड़ा, जबकि शरीर का दूसरा हिस्सा भी गंभीर रूप से घायल हो गया।

घटना के बाद किसान एवं समाजसेवी एम.एस. मेवाड़ा के

बेलगांव में सडक पर घायल मिले बाईक सवार

परासिया। न्यूटन पुलिस चौकी क्षेत्र के बेलगांव में अनखावाडी पुलिया के पास बाईक सवार सडक पर घायल मिले। दोनों घायलों को डायल 112 एफआरवी 13 से तत्काल अस्पताल लाया गया। पायलट अनिल पाल, आरक्षक विपिन पांडे की तत्परता से घायलों को समयपर अस्पताल पहुंचाकर जान बचाई गई। डायल 112 पर सूचना मिली की अनखावाडी पुलिया के पास दो लोग घायल पडे है। तत्काल डायल 112 एफआरवी 13 मौके पर पहुंची।

बीजकवाड़ा में तालाब के अंदर से डाल दी नल जल योजना की पाईप लाईन

परासिया। पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया ने ग्राम पंचायत बीजकवाड़ा की नल-जल योजना में पाइपलाइन बिछाने के कार्य में सुधार की मांग को लेकर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग की अनुविभागीय अधिकारी प्राची घुरे को मांग पत्र सौंपा। पीएचई एसडीओ को पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया ने बताया कि पाईप लाईन तालाब के अंदर से डाली गई है। इसे तालाब के बाहर से डाला जाना चाहिए। पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया ने बताया कि मन की बात कार्यक्रम के दौरान बीजकवाड़ा में नागरिकों ने इस समसया से अवगत कराया था। पेयजल योजना की पाइपलाइन तालाब के बाहर से बिछाने की जगह तालाब के अंदर से डाली गई है।

CHANGE OF NAME

I , ARMY NO - 14832788N RANK HAV/MT NAME KILARI MANJUNATH SOMAPPA PRESENTLY RESIDING AT GUDI ONI, KALABHAVI, BELGAUM, KARNATAKA, 591115 PRESENTLY WORKING AT 536 ASC BN (RAPID STRIKE) C/O 56 APO I DECLARE THAT MY CORRECT NAME IS KILARI MANJUNATH SOMAPPA , THE SAME NAME WAS MENTIONED IN MY AADHAR CARD, BUT IN MY ARMY SERVICE RECORD MY NAME WAS MENTIONED AS KILARI MANJUNATH , INSTEAD OF MENTIONING AS KILARI MANJUNATH SOMAPPA . VIDE AFFIDAVIT DATED 27/07/2026 EXECUTED BEFORE DISTRICT COURT SAGAR M.P

CHANGE OF NAME & DOB

I , SUSHITA DWIVEDI IS MOTHER OF NO - JC 571887X RANK SUB NAME SUNIL KUMAR DWIVEDI PERENT UNIT 11 MAHAR PRESENTLY SERVING IN 1 RR HOME ADDRESS AT 85 , WARD NO 11 , BADGAIYAN TOLA, MADWA - 493, PO - MADWA, DIST - REWA, STATE - MADHYA PRADESH, PIN -486550 HAVE CHANGED MY NAME FROM SUSHITA DWIVEDI TO SUSHEELA DWIVEDI AND CHANGED MY DOB FROM 19/02/1964 TO 01/01/1961 . VIDE AFFIDAVIT DATED 27/07/2026 EXECUTED BEFORE DISTRICT COURT SAGAR M.P

CHANGE OF NAME

I, NITESH KUMAR YADAV IS SON OF ARMY NO - 4576606Y RANK HAV NAME PRADIP KUMAR SERVING IN 1 MAHAR HOME ADDRESS AT 00, CHHOTI KHAJURI, KHAJURI, VARANASI, UTTAR PRADESH, 221307 HAVE CHANGED MY NAME FROM NITESH KUMAR YADAV TO NITESH KUMAR. VIDE AFFIDAVIT DATED 27/07/2026 EXECUTED BEFORE DISTRICT COURT OF SAGAR M. P

CHANGE OF NAME

I, ARMY NO - 15430217Y RANK HAV NAME RABINDRNATH JANA OF MILITARY HOSPITAL SAGAR C/O 56 APO HOME ADDRESS AT VILL - LALAT, PO - LALAT, PS - BELDA, DIST - PASCHIM MEDINIPUR, STATE - WEST BENGAL, PIN - 721443 THAT I HAVE CHANGED THE NAME OF MY FATHER FROM BHANU CHARAN JANA TO BHANU JANA . DUE TO AVOID ANY FUTURE CONTROVERSY VIDE AFFIDAVIT DATED 27/07/2026 EXECUTED BEFORE DISTRICT COURT SAGAR M.P

CHANGE OF NAME

I , ARMY NO - 14832788N RANK HAV/MT NAME KILARI MANJUNATH SOMAPPA PRESENTLY RESIDING AT GUDI ONI, KALABHAVI, BELGAUM, KARNATAKA, 591115 PRESENTLY WORKING AT 536 ASC BN (RAPID STRIKE) C/O 56 APO I DECLARE THAT MY WIFE CORRECT NAME IS KALPANA MANJUNATH KILARI , THE SAME NAME WAS MENTIONED IN HER AADHAR CARD , BUT IN MY ARMY SERVICE RECORD MY WIFE NAME MENTIONED AS KALPANA , INSTEAD OF MENTIONING AS KALPANA MANJUNATH KILARI . VIDE AFFIDAVIT DATED 27/07/2026 EXECUTED BEFORE DISTRICT COURT SAGAR M.P

CHANGE OF NAME

I , ARMY NO - 14832788N RANK HAV/MT NAME KILARI MANJUNATH SOMAPPA PRESENTLY RESIDING AT GUDI ONI, KALABHAVI, BELGAUM, KARNATAKA, 591115 PRESENTLY WORKING AT 536 ASC BN (RAPID STRIKE) C/O 56 APO I DECLARE THAT MY DAUGHTER CORRECT NAME IS SHAILAJA MANJUNATH KILARI , THE SAME NAME WAS MENTIONED IN HER AADHAR CARD, BUT IN MY ARMY SERVICE RECORD MY DAUGHTER NAME WAS MENTIONED AS SHAILAJA , INSTEAD OF MENTIONING AS SHAILAJA MANJUNATH KILARI . VIDE AFFIDAVIT DATED 27/07/2026 EXECUTED BEFORE DISTRICT COURT SAGAR M.P

कार्यालय नगर पालिका परिषद डोंगर परासिया, जिला –छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
Office of The Municipal Council Dongar Parasia Distt.Chhindwara (M.P)
Email :- cmopar-cdw@mp.gov.in ULB-802383 Phone :- 07161-220508
Website :- www.parasiya.mpenagarpalika.com

क्र/ 447 /न.पा.प./2026, डोंगर परासिया दिनांक:– 24/07/2026

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अमानक पॉलीथीन (120 माईक्रोन से कम) सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक के झण्डे, प्लास्टिक के स्टीकर, गुब्बारों में उपयोग होने वाली प्लास्टिक डंडियां, कैण्डी स्टिक, थर्माकोल की सजावट सामग्री, प्लास्टिक प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चाकू, स्ट्रा जैसे कटलरी, आईसक्रीम की डंडियां, मिठाई के डिब्बे के इर्द गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट (9,100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक) पी.वी.सी. बैनर, प्लास्टिक स्टार्टर का प्रयोग दुकानदार/नागरिक द्वारा विक्रय, भण्डारण, उद्योग एवं उपयोग प्रतिबंधित किया गया है, – ऐसा करते पाये जाने पर रूपये 200 से 1000/– रूपये जुर्माना निर्धारित किया गया है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद डोंगर परासिया
जिला – छिंदवाड़ा (म.प्र.)

गुरु पूर्णिमा पर ब्रम्ह आश्रम सांइ मंदिर में होगा अभिषेक

परासिया। गुरु पूर्णिमा पर गेस्ट हाउस के ब्रम्ह आश्रम सांई मंदिर वार्ड क्रमांक आठ 29 जुलाई बुधवार को साईं बाबा और बजरंग दादा का पूजन एवं अभिषेक किया जाएगा । मंदिर समिति के दर्शन अरोरा ने बताया कि इसके बाद महाआरती होगी । दिनभर छिंदवाड़ा जिले के कलाकारों द्वारा भजन कार्यक्रम होगा । दोपहर 2 बजे के बाद भंडारा वितरण होगा ।

कार्यालय नगर पालिका परिषद डोंगर परासिया, जिला –छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
Office of The Municipal Council Dongar Parasia Distt.Chhindwara (M.P)
Email :- cmopar-cdw@mp.gov.in ULB-802383 Phone :- 07161-220508
Website :- www.parasiya.mpenagarpalika.com

पत्र क्रमांक:450/न.प./2026 दिनांक: 24 / 07 /2026

अधिसूचना / सार्वजनिक सूचना

निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (C&D Waste) के वैज्ञानिक प्रबंधन, पुनः उपयोग एवं धूल नियंत्रण संबंधी

नगरीय निकाय क्षेत्र अंतर्गत संचालित समस्त नागरिकों, भवन निर्माताओं, ठेकेदारों, विकासकर्ताओं एवं कार्यदायी संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (Construction & Demolition Waste - C&D Waste Management Rules, 2016) का वैज्ञानिक प्रबंधन, पुनः उपयोग एवं धूल नियंत्रण सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है।

निर्माण कार्यों के उपरांत बची हुई सामग्री तथा विध्वंस (Demolition) से प्राप्त सामग्री जैसे—मलबा, ईंट, कंक्रीट, मिट्टी, पत्थर, टाइल्स आदि को खुले में फेंकना, नालियों/सार्वजनिक स्थलों/सड़कों पर डालना अथवा अवैज्ञानिक रूप से निस्तारित करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

आवश्यक निर्देश एवं पुनः उपयोग संबंधी नियम:

1. **सामग्री का पुनः उपयोग:** समस्त संबंधित ठेकेदार/एजेंसियाँ प्राप्त अपशिष्ट का अधिकतम पुनः उपयोग निम्न कार्यों में सुनिश्चित करें —
   - निम्न स्तर (निचले) क्षेत्रों में भराव (Filling) कार्य।
   - सड़क/मार्ग के सब-बेस अथवा लेवलिंग कार्य।
   - गड्ढों की भराई एवं भूमि समतलीकरण।
   - पुनर्चक्रण (Recycling) योग्य सामग्री का पृथक्करण एवं पुनः उपयोग।
2. **सुरक्षा एवं ढकाव:** निर्माण स्थल को चारों ओर से टीन शेड / ग्रीन नेट / कपड़े आदि से ढँककर ही कार्य किया जाए।
3. **सामग्री का भण्डारण:** निर्माण सामग्री जैसे—रेत, सीमेंट, मिट्टी एवं मलबा खुले स्थान पर न रखा जाए, उसे तिरपाल या शीट से ढँककर रखा जाए।
4. **धूल नियंत्रण:** निर्माण कार्य के दौरान धूल उड़ने से रोकने हेतु आवश्यकतानुसार नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाए।
5. **परिवहन सुरक्षा:** मलबे का परिवहन करते समय वाहन को पूरी तरह ढँककर ले जाया जाए, ताकि सड़क पर धूल या कचरा न फैले।
6. **संग्रहण एवं निस्तारण:** निर्माण कार्य से उत्पन्न मलबे का पृथक संग्रहण कर नगर परिषद द्वारा अधिकृत स्थान पर ही निस्तारण किया जाए।

विशेष नोट: *निर्देशों का पालन न किए जाने अथवा सार्वजनिक स्थानों पर मलबा फेंकने/प्रदूषण फैलाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध प्रचलित नियमों के अंतर्गत वैधानिक एवं दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।*

यह अधिसूचना जनहित में तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद डोंगर परसिया (म.प्र.)

महाकाल मंदिर में पहली बार मिलेगा दक्षिण भारतीय प्रसाद

मंगलवार और शुक्रवार को बदलेगा अन्न क्षेत्र का मेन्यू, देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगा पारंपरिक दक्षिण भारतीय भोजन

मध्य स्वर्णिम, उज्जैन।

श्री महाकालेश्वर मंदिर में देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अब अन्न क्षेत्र में दक्षिण भारतीय व्यंजनों का स्वाद भी मिलेगा। मंदिर समिति ने पहली बार निःशुल्क अन्न क्षेत्र में दक्षिण भारतीय पारंपरिक भोजन को प्रसादी के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के तहत मंगलवार और शुक्रवार को श्रद्धालुओं को अलग-अलग दक्षिण भारतीय व्यंजन परोसे जाएंगे। मंदिर समिति के निःशुल्क अन्न क्षेत्र में अब तक श्रद्धालुओं को दाल, चावल, गेहूं की रोटी, मौसमी सब्जियों और मिठाई सहित पारंपरिक भोजन प्रसादी के रूप में दिया जाता था। अब इसमें दक्षिण भारतीय व्यंजनों को भी शामिल किया गया है। मंदिर समिति का अन्न क्षेत्र पूरी तरह दान से संचालित होता है और यहां प्रतिदिन दो शिफ्ट में करीब 9 हजार श्रद्धालु भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक मंगलवार को श्रद्धालुओं को सांभर, इडली, स्टीम चावल, मौसमी सब्जी और पोंगल प्रसादी के रूप में परोसा जाएगा। मंदिर समिति का उद्देश्य देश के अलग-अलग हिस्सों से महाकाल दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन के माध्यम से दक्षिण भारतीय परंपरा और व्यंजनों से भी परिचित कराना है। इडली को चावल और उड़द दाल से तैयार कर भाप में पकाया जाता है और इसे सांभर के साथ परोसा जाता है। वहीं पोंगल चावल और मूंग दाल से तैयार होने वाला पारंपरिक दक्षिण भारतीय व्यंजन है। इसे नमकीन और मीठे दोनों रूपों में बनाया जाता है। प्रत्येक शुक्रवार को अन्न क्षेत्र में पुलिहोरा, पायसम, रसम, मौसमी सब्जी और स्टीम चावल प्रसादी के रूप में परोसे जाएंगे। पुलिहोरा इमली, नींबू या कच्चे आम और मसालों से तैयार किया जाने वाला खट्टा-चटपटा चावल का व्यंजन है। दक्षिण भारत में इसे कई स्थानों पर प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। पायसम दक्षिण भारत की प्रसिद्ध मीठी खीर है, जिसे दूध, चावल, सेवई या दाल और गुड़ अथवा चीनी से तैयार किया जाता है। वहीं रसम इमली, टमाटर और काली मिर्च-जीरे के स्वाद वाला खट्टा और मसालेदार व्यंजन है, जिसे आमतौर पर चावल के साथ खाया जाता है। श्री महाकालेश्वर मंदिर का निःशुल्क अन्न क्षेत्र श्रद्धालुओं और दानदाताओं के सहयोग से संचालित होता है। यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। भगवान महाकालेश्वर को सुबह करीब 10 बजे भोग अर्पित किए जाने के बाद श्रद्धालुओं को भोजन प्रसादी उपलब्ध कराई जाती है।

सीएम हेल्पलाइन की 50 दिन से अधिक लंबित शिकायतों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश

कलेक्टर सिंह ने समयावधि पत्रों और विभागीय योजनाओं की समीक्षा की

मध्य स्वर्णिम, उज्जैन।

कलेक्टर रौशन कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को प्रशासनिक संकुल भवन के सभाकक्ष में समयावधि पत्रों, सीएम हेल्पलाइन और विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागवार लंबित प्रकरणों, जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति और आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को लंबित मामलों का समय-सीमा में निराकरण करने और शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर सिंह ने 15 अगस्त को आयोजित होने वाले जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समय-सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए। वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए समारोह स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित करने को कहा गया।

उन्होंने जिला पंचायत, जनपद पंचायत और नगरीय निकायों में ध्वजारोहण के दौरान ध्वज संहिता का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही शहीदों के परिजनों को सम्मानपूर्वक समारोह स्थल तक लाने और उनके बैठने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। कलेक्टर ने राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले के सभी शासकीय भवनों पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आकर्षक रोशनी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मुख्य समारोह में साउंड और माइकिंग सिस्टम, साज-सज्जा तथा वीआईपी प्रोटोकॉल से जुड़ी व्यवस्थाएं उच्च गुणवत्ता की रखने को कहा गया। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल 13 अगस्त को आयोजित की जाएगी। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को अपनी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए समयावधि पत्रों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर सिंह ने सभी विभागों को निर्धारित अवधि में प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाना चाहिए और शिकायतकर्ताओं को समय पर राहत मिलनी चाहिए। उन्होंने प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई पर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों से कहा कि लंबित मामलों के निराकरण में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की विभागवार समीक्षा करते हुए लंबित शिकायतों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।

स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां समय-सीमा में पूरी करने के निर्देश

■ उन्होंने कम ग्रेडिंग वाले विभागों को अपने प्रदर्शन में सुधार कर ए ग्रेड हासिल करने के लिए गंभीरता से कार्य करने को कहा। उन्होंने 50 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। वहीं, जिन विभागों में बड़ी संख्या में शिकायतें लंबित हैं, उन्हें एक सप्ताह के भीतर सभी प्रकरणों का निराकरण करने को कहा गया। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में एक पेड़ मां के नाम अभियान की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर सिंह ने सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप समय पर पौधारोपण करने के निर्देश दिए। उन्होंने रोपित किए गए पौधों की जानकारी पोर्टल और वायुदूत ऐप पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने को कहा। उन्होंने अभियान में आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने और सामाजिक संस्थाओं को इससे जोड़ने पर जोर दिया। साथ ही पौधारोपण अभियान की नियमित मॉनिटरिंग करने और समय-समय पर प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने उच्च शिक्षा विभाग को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशेष पौधारोपण अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत विद्यार्थियों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जाए और अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएं।

नंदी महाराज का पूजन-अभिषेक किया

महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए फिल्म निर्माता भंडारकर

मध्य स्वर्णिम, उज्जैन।

प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक मधुर भंडारकर सोमवार तड़के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान महाकाल की प्रातःकालीन भस्म आरती में शामिल होकर पूजा-अर्चना की। करीब दो घंटे तक नंदी हॉल में बैठकर उन्होंने भस्म आरती के दिव्य दर्शन किए और भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। मधुर भंडारकर तड़के करीब 3 बजे इंदौर से उज्जैन पहुंचे। वे इंदौर में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे और वहां से सीधे महाकाल मंदिर पहुंचे। भस्म आरती के दौरान वे भगवान महाकाल की भक्ति में लीन नजर आए। भस्म आरती के बाद मधुर भंडारकर ने नंदी महाराज का पूजन-अभिषेक किया और नंदी के कान में अपनी मनोकामना कही। इसके बाद उन्होंने चांदी द्वार से पुजारी के माध्यम से भगवान महाकाल को जल अर्पित कर आशीर्वाद लिया। दर्शन के बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से उनका स्वागत और सम्मान भी किया गया। दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में मधुर भंडारकर ने कहा कि वे हर वर्ष भगवान महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आते हैं। उन्होंने कहा कि इंदौर में एक कार्यक्रम के सिलसिले में आए थे, इसलिए इस बार भी महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। महाकाल के दर्शन कर हमेशा आत्मिक शांति और खुशी मिलती है। खासकर युवा पीढ़ी को मंदिर में बम-बम भोले के जयकारे लगाते हुए देखना बेहद सुखद अनुभव होता है।

10 लाख की साइबर ठगी : फेसबुक लिंक से शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर फंसाया

मध्य स्वर्णिम, रतलाम।

शेयर मार्केट में निवेश कर कम समय में रकम दोगुनी करने के लालच में एक व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हो गया। फेसबुक पर मिली एक लिंक के जरिए साइबर ठगों ने निवेश पर अधिक मुनाफा देने का झांसा देकर पीड़ित से अलग-अलग किस्तों में 10 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा करा ली। जब पीड़ित ने निवेश की रकम वापस निकालने की कोशिश की तो संबंधित एप्लीकेशन बंद हो गई। इसके बाद उसे ठगी का अहसास हुआ और उसने साइबर सेल रतलाम में शिकायत दर्ज कराई। मामला स्टेशन रोड थाना क्षेत्र से जुड़ा है। पीड़ित ने 12 मार्च 2026 को साइबर सेल रतलाम में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया कि उसे फेसबुक पर एक लिंक प्राप्त हुई थी। लिंक के माध्यम से उसे शेयर मार्केट में निवेश करने और कम समय में अधिक लाभ कमाने का लालच दिया गया। ठगों के झांसे में आकर पीड़ित ने 27 फरवरी 2026 से 12 मार्च 2026 के बीच अलग-अलग किस्तों में 10 लाख रुपए से अधिक की राशि कथित निवेश के नाम पर जमा कर दी। ठग लगातार अधिक मुनाफा दिलाने का भरोसा देकर पीड़ित से और राशि निवेश करने के लिए कहते रहे। पीड़ित को जब लगा कि निवेश की गई राशि से अच्छा मुनाफा मिल चुका है, तो उसने रकम वापस निकालने का प्रयास किया। इसी दौरान संबंधित एप्लीकेशन अचानक बंद हो गई। इसके बाद पीड़ित को समझ आया कि वह साइबर ठगी का शिकार हो चुका है। ठगी का पता चलते ही उसने साइबर सेल रतलाम में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच शुरू की और शिकायत को नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज किया।

काल भैरव मंदिर को 10 लाख के बैरिकेड्स दान

उज्जैन। उज्जैन के काल भैरव मंदिर में सावन के दौरान बढ़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मुंबई के दो दानदाताओं ने मंदिर समिति को 10 लाख कीमत के बैरिकेड्स दान किए हैं। बैरिकेड्स की पहली खेप रविवार को उज्जैन पहुंची। रात में विधि-विधान से पूजन के बाद इन्हें मंदिर समिति को सौंप दिया गया। मुंबई निवासी मनीष पांचाल और समीर पांचाल ने नकद राशि देने के बजाय सीधे 10 लाख की लागत से बैरिकेड्स तैयार करवाकर मंदिर समिति को भेंट किए हैं। इन बैरिकेड्स का उपयोग सावन में श्रद्धालुओं की कतारों और भीड़ प्रबंधन के लिए किया जाएगा, जिससे दर्शन व्यवस्था अधिक सुगम हो सके। बैरिकेड्स सौंपने की प्रक्रिया एसडीएम एलएन गर्ग, पटवारी महेश देपन, मंदिर प्रबंधक संध्या मारकंडे और व्यवस्थापक अनिल बोरासी की मौजूदगी में पूरी हुई। एसडीएम एलएन गर्ग ने बताया कि फिलहाल 100 बैरिकेड्स मंदिर पहुंच चुके हैं। करीब 200 बैरिकेड्स की दूसरी खेप अगले 15 दिनों में मंदिर पहुंच जाएगी।

उज्जैन का सबसे बड़ा अत्याधुनिक ऑडिटोरियम गीता भवन बनकर तैयार, 1,250 लोगों की बैठने की क्षमता

मध्य स्वर्णिम, उज्जैन।

शहर का सबसे बड़ा अत्याधुनिक ऑडिटोरियम लगभग बनकर तैयार हो चुका है। इसे %गीता भवन% के नाम से जाना जाएगा। बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 1,250 लोगों की बैठने की क्षमता वाले इस ढाई मंजिला अत्याधुनिक ऑडिटोरियम का लोकार्पण कर सकते हैं। भवन के निर्माण का काम अंतिम चरण में है और शेष कार्यों को तय समय-सीमा में पूरा करने के लिए 100 से अधिक कारीगर दिन-रात जुटे हुए हैं। शनिवार को कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने देवास रोड स्थित विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की भूमि पर निर्मित गीता भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को शेष सभी काम 29 जुलाई से पहले पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान भवन में चल रहे फिनिशिंग कार्यों और अन्य व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली गई गीता भवन में फिलहाल बैठने की व्यवस्था, मुख्य प्रवेश द्वार पर पत्थर लगाने, मंच निर्माण और ऑडिटोरियम में कुर्सियां स्थापित करने सहित विभिन्न फिनिशिंग कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे किए जाएं, ताकि संभावित लोकार्पण कार्यक्रम से पहले भवन पूरी तरह तैयार हो सके। गीता भवन का निर्माण लगभग 5.1 हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 18 मार्च को इसके निर्माण के लिए भूमिपूजन किया था।

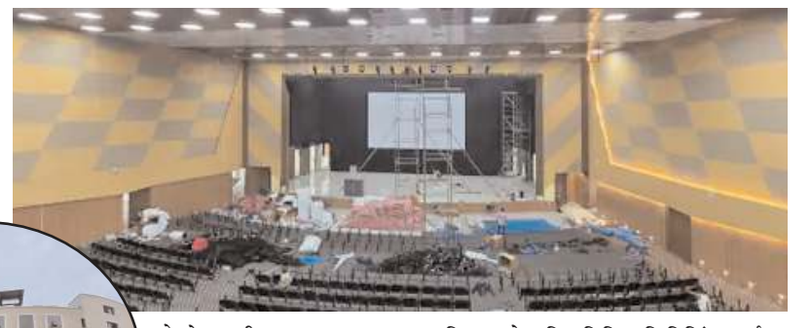

उज्जैन में 167वां आयकर दिवस मनाया गया करदाता हित और पारदर्शी कर प्रशासन पर जोर

मध्य स्वर्णिम, उज्जैन।

आयकर विभाग, उज्जैन द्वारा 167वां आयकर दिवस उत्साह और गरिमापूर्ण वातावरण में मनाया गया। आयकर कार्यालय परिसर में आयोजित समारोह की अध्यक्षता प्रधान आयकर आयुक्त (पु.ई.)-1 डॉ. राजा राम साह ने की। कार्यक्रम में विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारी और गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। समारोह में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष रवि अग्रवाल का विशेष संदेश प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही आयकर विभाग की उपलब्धियों, आधुनिक सेवाओं और करदाता हित में किए जा रहे प्रयासों पर आधारित लघु फिल्म भी दिखाई गई। कार्यक्रम के दौरान आयकर कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। अपने संबोधन में डॉ. राजा राम साह ने कहा कि आयकर दिवस केवल विभाग के स्थापना दिवस के रूप में मनाने का अवसर नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले ईमानदार करदाताओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने का भी महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने सरकार की करदाता हितैषी पहलों और डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कर प्रशासन को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि करदाताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। समारोह में आयकर विभाग के वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारियों ने अपने कार्यकाल के अनुभव साझा किए। उन्होंने डिजिटल इंडिया अभियान के तहत कर प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए आयकर विभाग की ओर से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। वक्ताओं ने कहा कि तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल से करदाताओं के लिए प्रक्रियाएं पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक हुई हैं।

सेवानिवृत्त अधिकारियों ने साझा किए अनुभव

■ समारोह के दौरान आयकर विभाग, उज्जैन ने करदाताओं को बेहतर और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ स्वैच्छिक कर अनुपालन को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। विभाग की ओर से लगातार आधुनिक तकनीक और डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे कर प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ करदाताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके। अधिकारियों ने कहा कि करदाताओं को समय पर और सरल तरीके से सेवाएं उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकताओं में शामिल है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि देश के विकास और राष्ट्र निर्माण में ईमानदार करदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। करदाताओं द्वारा समय पर कर का भुगतान किए जाने से सरकार को विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध होते हैं। ऐसे में करदाताओं और आयकर विभाग के बीच विश्वास, पारदर्शिता और सहयोग का मजबूत होना बेहद जरूरी है। विभाग की ओर से करदाताओं को यह भरोसा भी दिलाया गया कि उनकी समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए आवश्यक कदम लगातार उठाए जा रहे हैं।

सप्ताह में दो बार मिल रहा मुफ्त डायलेसिस

आयुष्मान योजना बनी सहारा, शासकीय अस्पताल में मिल रही निःशुल्क डायलेसिस सुविधा

मध्य स्वर्णिम, उज्जैन।

आयुष्मान भारत निरामयम योजना जरूरतमंद मरीजों के लिए बड़ी राहत का माध्यम बन रही है। योजना के तहत संचालित शासकीय डायलेसिस यूनिट में गंभीर किडनी रोग से पीड़ित मरीजों को निःशुल्क डायलेसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उज्जैन के वेदनगर निवासी 54 वर्षीय श्रीमती शीला भी इसी योजना का लाभ लेकर नियमित उपचार करा रही हैं। वर्तमान में सिविल अस्पताल माधवनगर में उनका सप्ताह में दो बार निःशुल्क डायलेसिस किया जा रहा है। शीला लंबे समय से उच्च रक्तचाप, पूरे शरीर में सूजन और लगातार बिगड़ते स्वास्थ्य से परेशान थीं। तबीयत अधिक खराब होने पर परिजन उन्हें जांच के लिए निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद किडनी की गंभीर समस्या बताई और तत्काल डायलेसिस शुरू कराने की सलाह दी। परिवार ने किसी तरह आर्थिक व्यवस्था कर निजी अस्पताल में उपचार शुरू कराया। लेकिन सप्ताह में दो बार डायलेसिस कराने के कारण हर सप्ताह करीब तीन से चार हजार रुपये का खर्च आने लगा। लगातार होने वाले इस खर्च से परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ने लगा और नियमित उपचार जारी रखना चुनौती बनता जा रहा था। इसी दौरान क्षेत्र की स्वास्थ्य एवं आशा कार्यकर्ता ने शीला के परिजनों को सिविल अस्पताल माधवनगर में उपलब्ध आयुष्मान भारत निरामयम योजना और शासकीय डायलेसिस सुविधा के बारे में जानकारी दी। इसके बाद परिजन शीला को सिविल अस्पताल माधवनगर लेकर पहुंचे अस्पताल में उनकी पात्रता की जांच की गई और आयुष्मान योजना के तहत उनका पंजीयन किया गया। प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनका निःशुल्क उपचार शुरू कर दिया गया। अब शीला को अस्पताल की शासकीय डायलेसिस यूनिट में नियमित रूप से सप्ताह में दो बार डायलेसिस की सुविधा मिल रही है।

मूंग खरीदी पदयात्रा से पहले पुलिस-प्रशासन अलर्ट इटारसी-नर्मदापुरम मार्ग पर पुलिस की चेकिंग

मध्य स्वर्णिम, इटारसी।

संयुक्त किसान मोर्चा की मूंग खरीदी की मांग को लेकर प्रस्तावित पदयात्रा से पहले सोमवार को इटारसी-नर्मदापुरम मार्ग पर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आया। कृषि उपज मंडी के पास भैरव बाबा मंदिर के समीप भारी पुलिस बल तैनात किया गया। यहां पुलिस ने आने-जाने वाले वाहनों की सघन जांच की और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी। प्रशासन की ओर से किसान नेताओं की गतिविधियों की भी लगातार निगरानी की जा रही है। प्रस्तावित किसान पदयात्रा को देखते हुए प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इटारसी, रामपुर, केसला और तवानगर थाना क्षेत्रों के पुलिस बल को सक्रिय किया है। प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। पुलिस टीमों को प्रमुख मार्गों पर लगातार निगरानी रखने और संदिग्ध गतिविधियों की तत्काल जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।

दक्ष प्रजापति जयंती पर रैली

इटारसी। इटारसी में सोमवार को भगवान महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती पर सोमवार को प्रजापति समाज ने शहर में पहली बार वाहन रैली निकाली। रैली के माध्यम से समाज ने एकता और संगठन का संदेश दिया। इसमें युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और समाज के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। रैली की शुरुआत खेड़ापति मंदिर (सीपीई पुरानी इटारसी) से हुई। एक बग्गी में महाराजा दक्ष प्रजापति की तस्वीर सजाई गई थी। समाजजन पीले साफे पहनकर जयघोष लगाते हुए रैली में शामिल हुए। रैली में दोपहिया और चारपहिया वाहनों पर महाराजा दक्ष प्रजापति के चित्र वाले बैनर और भगवा ध्वज लगाए गए थे। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती रैली में धार्मिक और सामाजिक उत्साह का माहौल नजर आया। वाहन रैली जयस्तंभ चौक पहुंची, जहां युवाओं ने भक्ति गीतों पर नृत्य किया। इस दौरान पुष्पवर्षा कर रैली का स्वागत किया गया। शहर के अलग-अलग स्थानों पर लोगों ने भी पुष्पवर्षा कर समाजजनों का उत्साह बढ़ाया। रैली रेलवे स्टेशन रोड स्थित हनुमान मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। समाज पदाधिकारियों ने बताया कि महाराजा दक्ष प्रजापति समाज के आराध्य देव हैं। जयंती पर पहली बार आयोजित वाहन रैली का उद्देश्य समाज को संगठित करना, युवाओं को संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना और सामाजिक एकता का संदेश देना है। आयोजन के दौरान अनुशासन और उत्साह देखने को मिला। समाज के वरिष्ठजनों और युवाओं ने रैली में शामिल सभी समाजबंधुओं का आभार जताया।

खाद वितरण व्यवस्था सुधारने की मांग पर संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन

बैरिकेड तोड़ भोपाल की ओर बढ़े किसान, बुधनी में रुके एसपी के पैरों में गिरा किसान, अफसर ने गले लगाया

मध्य स्वर्णिम, नर्मदापुरम।

मध्यप्रदेश में मूंग की 100 प्रतिशत खरीदी और खाद वितरण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों का भोपाल कूच सोमवार को दिनभर तनावपूर्ण रहा। नर्मदापुरम में किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग पार कर भोपाल की ओर बढ़ने की कोशिश की। नर्मदा ब्रिज से पहले पुलिस और किसानों के आमने-सामने आने के बाद काफी देर तक बातचीत का दौर चला। देर शाम प्रशासन और किसान नेताओं के बीच चर्चा के बाद किसान बुधनी में रात्रि विश्राम के लिए तैयार हुए। मंगलवार सुबह किसान एक बार फिर भोपाल की ओर पैदल मार्च शुरू करेंगे। भोपाल कूच के लिए सोमवार सुबह नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर बड़ी संख्या में किसान एकत्र हुए। किसानों ने हनुमान चालीसा पाठ और सत्यनारायण कथा के साथ आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की और इसके बाद नारेबाजी करते हुए भोपाल की ओर पैदल मार्च शुरू किया। किसानों का कहना है कि मूंग खरीदी की व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण कई किसान अपनी उपज बेच नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा खाद लेने में भी किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सेठानी घाट से पूजा-पाठ के बाद शुरू हुआ मार्च

■ इन्हीं मांगों को लेकर किसान सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए भोपाल जाना चाहते थे। किसानों के मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने नर्मदापुरम के भोपाल चौराहे पर बैरिकेडिंग की थी। पुलिस अधिकारियों ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान भोपाल जाने की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद किसानों ने बैरिकेड पार कर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। स्थिति को देखते हुए नर्मदा ब्रिज और नर्मदापुरम-सीहोर सीमा पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। मौके पर आईजी, डीआईजी, कलेक्टर और एसपी सहित प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे। अधिकारियों ने किसान नेताओं से बातचीत कर स्थिति को नियंत्रित करने और आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास किया।

भोपाल चौराहे पर पुलिस ने रोका, बैरिकेड पार कर आगे बढ़े किसान

■ आंदोलन के दौरान सबसे भावुक दृश्य उस समय सामने आया, जब पुलिस अधिकारियों से बातचीत के बीच एक किसान अचानक एसपी साईं कृष्णा एस. थोटा के पैरों में गिर गया। किसान की भावुक स्थिति देखकर एसपी ने उसे उठाया और गले लगाकर शांत कराने की कोशिश की। आसपास मौजूद किसानों और पुलिसकर्मियों ने भी किसान को संभाला। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। किसानों का कहना था कि यह केवल एक किसान की परेशानी नहीं है, बल्कि प्रदेशभर के किसानों की समस्या है। उन्होंने सरकार से मूंग की पूरी खरीदी सुनिश्चित करने और खाद वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने की मांग की।

बातचीत के बाद बुधनी में रुके किसान

■ नर्मदा ब्रिज के पास पुलिस और किसानों के बीच काफी देर तक बातचीत चली। प्रशासन और किसान नेताओं के बीच चर्चा के बाद किसानों ने सोमवार रात बुधनी में रुकने पर सहमति जताई। अब मंगलवार सुबह किसान एक बार फिर भोपाल की ओर पैदल मार्च शुरू करेंगे। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसान सरकार से मूंग की शत-प्रतिशत खरीदी और खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं।

शराब के विवाद में पाइप और थप्पड़ से दो युवकों की बेरहमी से पिटाई

बहुत मार लिया, अब बस करो...-

मध्य स्वर्णिम, नर्मदापुरम।

इटारसी रोड स्थित पवारखेड़ा शराब दुकान के सामने रविवार को दो युवकों की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो देर रात सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें चार युवक दोनों युवकों के बाल पकड़कर उन्हें होस पाइप, थप्पड़ और लात-घूंसों से पीटते नजर आ रहे हैं। वीडियो में पीड़ित युवक लगातार छोड़ने की गुहार लगाते दिखाई दे रहे हैं। मामले में देहात थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वायरल वीडियो में कुछ युवक दोनों पीड़ितों को पकड़कर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान उनके साथ मारपीट की जा रही है। वीडियो में बीच-बचाव कर रहे कुछ लोग आरोपियों से कहते सुनाई दे रहे हैं बहुत मार लिया, अब बस करो। इसके बावजूद मारपीट करने वाले युवक रुकते नहीं हैं और दोबारा हमला करते दिखाई देते हैं। इस दौरान एक पीड़ित युवक कहता सुनाई देता है- ÷क्या मार ही डालोगे... बाल छोड़ो, तुम गलत कर रहे हो।÷ आरोप है कि इसके बाद भी आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट जारी रखी। पलासडोह गांव निवासी आदित्य गांगुलिया ने बताया कि उसका भाई सौरभ गांगुलिया अपने साथी विनोद बकोरिया के साथ शराब दुकान के बाहर बैठा था। दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान दुकान के अंदर से एक युवक बाहर आया और शराब पिलाने की बात कही।

मंदिर परिसर हर-हर महादेव से गूंजा

बारिश के लिए शिवलिंग को जल में डुबोया जल्द मेघ बरसाने के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना

मध्य स्वर्णिम, इटारसी।

बारिश की कमी के चलते किसानों की बढ़ती चिंता के बीच इटारसी के तिलक सिंदूर क्षेत्र स्थित प्राचीन तिलक सिंदूर मंदिर में रविवार को भगवान भोलेनाथ का विशेष जलाभिषेक और धार्मिक अनुष्ठान किया गया। बम बाबा समिति की ओर से आयोजित इस अनुष्ठान में अच्छी बारिश, किसानों की समृद्धि और क्षेत्र में खुशहाली की कामना की गई। इस दौरान शिवलिंग को पूरी तरह जल में डुबो दिया गया।

श्रद्धालुओं का मानना है कि भगवान भोलेनाथ को जल में विराजमान करने से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और क्षेत्र में अच्छी वर्षा होती है। इसी मान्यता के चलते रविवार सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। इस दौरान भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और विशेष पूजा-अर्चना की गई। इसके बाद शिवलिंग को जल में डुबोकर सामूहिक रूप से प्रार्थना की गई कि क्षेत्र में जल्द अच्छी बारिश हो, जिससे खेतों में खड़ी फसलों को पर्याप्त पानी मिल सके और किसानों को राहत मिले। धार्मिक अनुष्ठान के दौरान मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल बना रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाए। पूरा मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से गूंजता रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से क्षेत्र में जल्द अच्छी बारिश होने की प्रार्थना की। लोगों का कहना था कि समय पर बारिश होने से किसानों की खरीफ फसलों को राहत मिलेगी और क्षेत्र में खुशहाली आएगी। इटारसी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है।

इटारसी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने लिए 12 सैंपल

इटारसी। खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने सोमवार को इटारसी में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए निरीक्षण किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी भोजराज सिंह धाकड़ और कमलेश एस. दियावार की टीम ने बसंत बेकरी, पूरी लाइन स्थित जैसवाल किराना स्टोर और नारायण बेकरी पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान टीम ने संदेह के आधार पर दूध, दही, पनीर, छाछ और बेसन के कुल 12 नमूने एकत्र कर परीक्षण के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेज दिए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित विक्रेताओं पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि जिले में मिलावट रोकने और आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

15 पंचायतों में किसान पाठशाला सह ग्राम सभा का आयोजन, 31 जुलाई फसल बीमा की अंतिम तिथि

मध्य स्वर्णिम, नर्मदापुरम।

कलेक्टर सोमेश मिश्रा के निर्देश और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में पिपरिया अनुभाग की तहसील पिपरिया और बनखेड़ी की ग्राम पंचायतों में नारबाई प्रबंधन एवं फसल बीमा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अंतिम दिन रविवार 26 जुलाई को शेष बची 15 पंचायतों में गांव-गांव जाकर किसान पाठशाला सह ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इसमें किसानों को फसल बीमा योजना, फसल अवशेष प्रबंधन और कृषि से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। ग्राम सभा के दौरान किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी देते हुए बताया गया कि योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। योजना का लाभ ऋणी और अऋणी दोनों प्रकार के किसान ले सकते हैं। किसानों से समय-सीमा के भीतर अपना पंजीकरण कराने की अपील की गई। किसानों को बताया गया कि वे नजदीकी बैंक, सहकारी समिति या सीएससी सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि संबंधी दस्तावेज जैसे खसरा-खतौनी और बुवाई का प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा। ग्राम सभा में किसानों को बताया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सूखा, अतिवृष्टि, बाढ़ और कीटों के प्रकोप जैसी परिस्थितियों से फसलों को होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। अधिकारियों ने किसानों से योजना का लाभ लेने के लिए समय पर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की। किसान पाठशाला के दौरान किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन और नारबाई प्रबंधन के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। किसानों को बताया गया कि फसल कटाई के बाद खेतों में बचे अवशेष और पराली को जलाने के बजाय उचित प्रबंधन किया जाए।

बिजली कटौती से नाराज कॉलोनीवासी एमपीईबी दफ्तर पहुंचे, सलपटा फीडर से सप्लाई पर विरोध

बिहारी कॉलोनी में रोज 10 से 12 घंटे बिजली गुल रहने का आरोप

मध्य स्वर्णिम, इटारसी।

अघोषित बिजली कटौती और फीडर बदलने से नाराज बिहारी कॉलोनी के बड़ी संख्या में रहवासी सोमवार को पथरोटा स्थित बिजली वितरण कंपनी (एमपीईबी) के कार्यालय पहुंचे। रहवासियों ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर अघोषित बिजली कटौती तत्काल बंद करने, कॉलोनी की बिजली सप्लाई को दोबारा मेन फीडर से जोड़ने और बिजली दरों में कथित विसंगति दूर करने की मांग की। रहवासियों ने बताया कि पहले बिहारी कॉलोनी को पथरोटा के मेन फीडर से नियमित बिजली सप्लाई मिलती थी। हाल ही में कॉलोनी की बिजली सप्लाई को बदलकर सलपटा फीडर से जोड़ दिया गया। इसके बाद से कॉलोनी में रोजाना 10 से 12 घंटे तक बिजली गुल रहने की समस्या सामने आ रही है। कॉलोनीवासियों का कहना है कि लंबे समय तक बिजली बंद रहने के कारण लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। खासकर मजदूर वर्ग के परिवारों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

बिजली कटौती के कारण पेयजल व्यवस्था सहित अन्य जरूरी काम भी प्रभावित हो रहे हैं। बिहारी कॉलोनी के सुनील वर्मा ने बताया कि रहवासियों की ओर से दिए गए ज्ञापन में बिजली सप्लाई और बिलिंग को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। उनका आरोप है कि कॉलोनी को ग्रामीण फीडर से बिजली सप्लाई दी जा रही है, जबकि उपभोक्ताओं से अब भी शहरी दरों के हिसाब से बिजली बिल वसूला जा रहा है।

फीडर बदलने के बाद बढ़ी बिजली कटौती

■ रहवासियों ने इसे अनुचित बताते हुए बिजली सप्लाई व्यवस्था और बिलिंग की स्थिति की जांच कर आवश्यक सुधार करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि कॉलोनी की बिजली सप्लाई ग्रामीण फीडर से की जा रही है तो बिजली दरों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। कॉलोनीवासियों ने बिजली विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू करने के लिए मजबूर होंगे। रहवासियों ने अघोषित बिजली कटौती बंद करने और नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। ज्ञापन की प्रतियां एसडीएम इटारसी, डिविजनल इंजीनियर, सहायक इंजीनियर और सब-इंजीनियर एमपीईबी, थाना प्रभारी पथरोटा सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई हैं।

किसान आंदोलन से पहले भाकियू उपाध्यक्ष नजरबंद, सड़क पर किया हनुमान चालीसा पाठ

मध्य स्वर्णिम, सिवनी मालवा।

संयुक्त किसान मोर्चा की प्रस्तावित किसान क्रांति पदयात्रा और मुख्यमंत्री आवास के घेराव से पहले पुलिस-प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पटवारे को पुलिस ने उनके गांव भैरोपुर से लाकर सिवनी मालवा के रेस्ट हाउस में नजरबंद कर दिया। वहीं, डोलरिया में करीब 30 किसान कार्यकर्ताओं को पदयात्रा में शामिल होने से रोक दिया गया। इसके विरोध में कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पटवारे को उनके गांव भैरोपुर से लाकर सिवनी मालवा के रेस्ट हाउस में रखा है। उनकी निगरानी के लिए एडिशनल एसपी कमलेश खरपूसे, थाना प्रभारी सुधाकर बारसकर सहित पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस-प्रशासन की कार्रवाई के बाद पटवारे ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की आवाज दबाने के लिए उन्हें आंदोलन में शामिल होने से रोक रही है।

उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों को पूरा करने के बजाय उन्हें नजरबंद किया जा रहा है। पटवारे ने कहा कि इसके बावजूद किसान अपने अधिकारों की लड़ाई जारी रखेंगे। डोलरिया तहसील में क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के करीब 30 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किसान क्रांति पदयात्रा में शामिल होने से रोक दिया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने किसानों की मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी की।

मध्य स्वर्णिम ब्रीफ

वरिष्ठ सचिव समिति का पुनर्गठन

भोपाल। राज्य शासन द्वारा वरिष्ठ सचिव समिति का पुनर्गठन किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार समिति में मुख्य सचिव के साथ ही सचिव सामान्य प्रशासन, सचिव वित्त, सचिव विधि एवं विधायी कार्य, संजय दुबे अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास(मुख्य सचिव द्वारा नामित) एवं अमित राठौर प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। आदेश अनुसार विषय से संबंधित भारसाधक सचिव समिति में सदस्य एवं प्रस्तुतकर्ता होंगे। विधायी प्रस्तावों के परीक्षण के लिए भारसाधक सचिव, संसदीय कार्य विभाग, अतिरिक्त रूप से समिति के सदस्य होंगे। नीतिगत मामले एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर आवश्यकता होने पर एक या अधिक भारसाधक सचिव विशेष रूप से आमंत्रित किये जा सकेंगे। समिति के कार्यक्षेत्र में विस्तार अनुसार विधायी प्रस्तावों का परीक्षण, नीतिगत मामले तथा अन्य महत्वपूर्ण विषय जो मुख्यमंत्री अथवा मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किए गये हो प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

आयुष्मान भारत 'निरामयम्' के तहत एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों को मिलेगी सहज संबद्धता

भोपाल। आयुष्मान भारत निरामयम् मध्यप्रदेश के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय समिति (एसईसी) ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत पूर्ण एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों को बिना भौतिक निरीक्षण के योजना में संबद्धता प्रदान की जाएगी। साथ ही, उनकी एनएबीएच मान्यता के अनुरूप विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को भी स्वीकृति दी जाएगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी अरविंद शाह ने बताया कि इस व्यवस्था से अस्पतालों की संबद्धता प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध होगी। साथ ही प्रदेश के आयुष्मान हितग्राहियों को गुणवत्तापूर्ण एवं विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुगमता से उपलब्ध हो सकेंगी। यह निर्णय प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के मानकीकरण, गुणवत्ता संवर्धन और हितग्राही-केंद्रित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करेगा।

श्रम प्रहरी अभियान से जुड़ें, मध्यप्रदेश को बाल श्रम मुक्त बनाएं

भोपाल। श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों की सुरक्षा, बाल श्रम उन्मूलन एवं सुरक्षित कार्यस्थलों के निर्माण के उद्देश्य से श्रम प्रहरी अभियान संचालित किया जा रहा है। यह अभियान नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से श्रमिक हितों की रक्षा और श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अभियान के अंतर्गत नागरिकों से अपील की गई है कि यदि उनके आस-पास कोई अपंजीकृत कारखाना, अवैध औद्योगिक इकाई, असुरक्षित कार्यस्थल अथवा बाल श्रम से संबंधित कोई मामला दिखाई देता है, तो उसकी सूचना तत्काल श्रम विभाग को दें। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर विभाग द्वारा आवश्यक जांच एवं वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नागरिक श्रम विभाग के पोर्टल www.labour.mp.gov.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं अथवा श्रमिक हेल्पलाइन 1800-233-8888 पर सूचना दे सकते हैं।

दतिया में छह व्यक्तियों पर जिला बदर की कार्यवाही

भोपाल। दतिया में होने वाले विधानसभा उप निर्वाचन 2026 को शांति पूर्ण रूप से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक दतिया के प्रतिवेदन के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट स्वप्निल वानखड़े द्वारा 06 व्यक्तियों पर जिला बदर की कार्यवाही की गई है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनावेदक कृष्णपाल सिंह गुर्जर पुत्र लक्ष्मण सिंह गुर्जर निवासी ग्राम महुआ थाना सिविल लाईन दतिया, रमन पुत्र रामकुमार भार्गव उर्फ बबलू निवासी ग्राम उदगुंवा थाना जिगना, चिम्मू उर्फ तिलक सिंह यादव पुत्र रमेश यादव निवासी निदान का कुंआ दतिया थाना सिविल लाईन, उद्यम कुशवाहा पुत्र हरदास कुशवाहा निवासी ग्राम उनाव थाना उनाव, कारू उर्फ दीपक पुत्र राजेन्द्र सिंह गुर्जर निवासी ग्राम जैतपुरा थाना धीरपुरा, ब्रजेश पुत्र सिरनाम लोधी निवासी ग्राम हसनुपर थाना बसई के विरूद्ध यह कार्रबाई की गई है। म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 धारा 3 की सहपठित धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक को एक-एक माह तक कालावधि के लिए जिला दतिया एवं उससे लगे अन्य जिले शिवपुरी, ग्वालियर, भिण्ड़ जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने का निष्कासन आदेश जारी किया है।

ब्रिक्स देशों का संस्कृति सम्मेलन 5 से 8 अगस्त तक भोपाल में होगा

ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्री एवं प्रतिनिधि होंगे शामिल

भोपाल मध्य स्वर्णिम।

प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन (BRICS Culture Track Meetings) आगामी 5 अगस्त से 8 अगस्त तक भोपाल में आयोजित होगा, इसमें ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्री और प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। ब्रिक्स देशों के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी की जाएगी।

संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने सोमवार को कमिश्नर कार्यालय में सम्मेलन की तैयारियां की विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर संचालक संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार श्रीमती प्रियंका चंद्र (वी.सी के माध्यम से), कलेक्टर भोपाल प्रियंक मिश्रा, स्मार्ट सिटी सीईओ श्रीमती अंजू अरूण कुमार, संयुक्त आयुक्त डॉ. विनोद यादव, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती इला तिवारी, पुरातत्व विभाग, संस्कृति विभाग, एमएचएआई सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

संभागायुक्त शर्मा ने निर्देश दिए कि सम्मेलन की सभी व्यवस्थाएं भारत की संस्कृति, गौरव एवं परम्परा के अनुरूप उत्कृष्ट हों। उन्होंने माइक्रो प्लानिंग पर जोर देते हुए केन्द्र एवं राज्य शासन के सभी अधिकारियों को पूर्ण समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। प्रस्तावित कार्यक्रम अनुसार ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन में 5 अगस्त को ब्रिक्स देशों की तकनीकी समितियों की मिंटो हॉल में बैठक होगी। सायंकाल सदस्यगण इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का भ्रमण करेंगे। 6 अगस्त को पुन: ब्रिक्स देशों की तकनीकी समितियों की मिंटो हॉल में बैठक होगी. सायंकाल

रवीन्द्र भवन में ब्रिक्स कल्चरल फेस्टीवल में ब्रिक्स देशों के कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां होंगी। 7 अगस्त को ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों का आगमन होगा और उसके पश्चात वे भोपाल में ट्राइबल म्यूजिनियम, वन विहार एवं राज्य संग्रहालय का भ्रमण करेंगे। शाम 5 बजे से 7 बजे तक रवीन्द्र भवन में ब्रिक्स कल्चरल फेस्टीवल एवं कल्चरल शो का आयोजन किया जाएगा।

बाघ सप्ताह के अंतर्गत वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में पॉम पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन

भोपाल। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर बाघों के सम्बध में जनमानस एवं विद्यार्थियों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में बाघ सप्ताह का आयोजन 22 जुलाई से 28 जुलाई 2026 तक किया जा रहा है, जिसमें भोपाल शहर के महाविद्यालय/विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिये विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। बाघ सप्ताह के अतर्गत वन विहार संचालक विजय कुमार के निर्देशन में 27 जुलाई को प्रात: 10 बजे से 12 बजे तक विहार स्थित विहार वीथिका में सेंट जॉर्ज स्कूल, जवाहर लाल स्कूल एवं गुरूनानक पब्लिक स्कूल के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिये मध्यप्रदेश में बाघ विषय पर पॉम पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में 50 प्रतिभागी एवं शिक्षकों ने भाग लिया। विजयी प्रतिभागियों को प्रथम द्वितीय, तृतीय को पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र तथा चार प्रतिभागियों को सात्वना पुरस्कार वन विहार सहायक सचालक डॉ. रूही हक प्रदान किये।

मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी को विश्वस्तरीय संरक्षण एवं पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा: शुक्ल

व्हाइट टाइगर सफारी के विस्तार एवं उन्नयन के दिए निर्देश

भोपाल मध्य स्वर्णिम।

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी के उन्नयन एवं विस्तार कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को मास्टर प्लान के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी का विस्तार केवल पर्यटन की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन, अनुसंधान और जन-जागरूकता को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम है। बैठक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) श्रीमती समीता राजौरा भी उपस्थित थी।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी मध्यप्रदेश की विशिष्ट पहचान है और इसे राष्ट्रीय स्तर का उत्कृष्ट वन्यजीव संरक्षण एवं इको-टूरिज्म केंद्र बनाया जाए। बैठक में वर्ष 2026-27 से 2045-46 तक की अवधि के लिए तैयार मास्टर प्लान की समीक्षा की गई। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार इस मास्टर प्लान में वर्तमान 121.99 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ 119.87 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल करते हुए कुल 241.86 हेक्टेयर में सफारी के विस्तार का प्रस्ताव है।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने निर्देश दिए कि प्रस्तावित विकास कार्यों में आधुनिक एवं प्राकृतिक वातावरण वाले पशु बाड़ों, संरक्षण प्रजनन केंद्रों, वन्य जीव रेस्क्यू सुविधाओं, पर्यटकों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाओं तथा प्रकृति एवं वन्यजीव संरक्षण पर आधारित इंटरएक्टिव एजुकेशन सेंटर की स्थापना को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान के प्रत्येक चरण का क्रियान्वयन केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के मानकों के अनुरूप किया जाए और पशु कल्याण, प्राकृतिक आवास आधारित डिज़ाइन, पर्यावरणीय स्थिरता और विज़िटर मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाए।

एग्री-हॉर्टिकल्चर सेक्टर में म.प्र. को मिला प्रथम पुरस्कार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उत्कृष्ट प्रदर्शन पर दी बधाई

भोपाल। नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं उद्यानिकी एक्सपो-2026 में संपूर्ण एग्री-हॉर्टिकल्चर सेक्टर में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मध्यप्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस उपलब्धि के लिये प्रदेश के किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और विभागीय अधिकारियों को बधाई दी है। अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो 25 से 27 जुलाई तक भारत मंडपम में आयोजित किया गया, जिसमें देश-विदेश से कृषि, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़े विभागों, वैज्ञानिकों, कृषि विशेषज्ञों, उद्यमियों तथा किसानों ने सहभागिता की। मुख्यमंत्री डॉ.

यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। किसान भाइयों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके इसके लिये सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और उत्पादित माल के विक्रय के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में किये गये नवाचारों को नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं उद्यानिकी एक्सपो-2026 में पूरे देश ने सराहा है। राज्य सरकार लगातार इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश उद्यानिकी क्षेत्र में लगातार नये कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रदेश में उद्यानिकी फसलों के उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, वैल्यू एडिशन, निर्यात संवर्धन और किसान हितैषी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है।

प्रधानमन्त्री के 'मन की बात' में सीधी में 15 सौ तालाब बनाने का झूठा दावा: अजय सिंह

भोपाल। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम में सीधी जिले में लगभग 15 सौ तालाब बनाने के दावे को पूरी तरह हवा-हवाई और हकीकत से परे बताया है। उन्होंने कहा कि किसी भी जिले में एक साथ 15 सौ खेत तालाबों का निर्माण होना बड़ी बात है, लेकिन यदि वास्तव में धरातल पर इतने तालाब बने होते तो सीधी की जनता को कहीं न कहीं दिखाई जरुर देते। सिंह ने मांग की है कि 'मन की बात' में प्रचारित किए गए इन सभी 1500 तालाबों की वास्तविक स्थिति, संबंधित ग्राम पंचायत का नाम, उनके निर्माण की तिथि और कुल निर्माण लागत से जुड़े सभी आंकड़े तुरंत सार्वजनिक किए जाएं। जानकारी सार्वजनिक होने से सीधी जिले के ग्रामवासी खुद मौके पर जाकर इन तालाबों के अस्तित्व की सच्चाई देख सकेंगे और सरकार के दावों की असलियत सामने आ सकेगी। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नजर नहीं आ रही है7 जिससे अंदेशा होता है कि केवल कागजों पर ही तालाबों की स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं।

प्रदेश की मंडियों में लगेंगी ग्रेडिंग सोर्सिंग यूनिट

भोपाल। प्रदेश की मंडियों में जल्दी ही ग्रेडिंग सोर्सिंग यूनिट काम करने लगेगी। प्रबंध संचालक कुमार पुरुषोत्तम ने आज समीक्षा बैठक में समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की वर्चुअल बैठक मंत्रालय वल्लभ भवन से आयोजित की गई जिसमें सभी अधिकारी कर्मचारी तथा 259 मंडियों के सचिव तथा सातों आंचलिक कार्यालय के संयुक्त संचालक झ्ष्ट के माध्यम से जुड़े।

युवा संगम : लाखों युवाओं के सपनों को मिल रही नई उड़ान, रोजगार और स्व-रोजगार का बना सशक्त मंच

भोपाल। युवाओं को एक ही स्थान पर रोजगार, स्व-रोजगार, अप्रेंटिसशिप और शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सके, इसी उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई युवा संगम पहल आज युवाओं के लिए अवसरों का सशक्त मंच बनकर उभरी है। गत नवंबर 2024 से जून 2026 तक प्रदेश के सभी जिलों में 1012 युवा संगम आयोजित किए गये हैं। इन आयोजनों के माध्यम से 3 लाख 62 हजार 799 युवाओं को रोजगार, स्व-रोजगार और अप्रेंटिसशिप से जोड़ा गया है। इनमें 1 लाख 81 हजार 248 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के ऑफर लेटर, 17 हजार 887 युवाओं का अप्रेंटिसशिप के लिए चयन तथा 1 लाख 63 हजार 664 युवाओं को स्व-रोजगार योजनाओं का लाभ मिला है। राज्य सरकार की यह पहल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ प्रदेश में रोजगारोन्मुख वातावरण तैयार करने की दिशा में प्रभावी भूमिका निभा रही है। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के संयुक्त प्रयास से नवंबर 2024 से प्रदेश के प्रत्येक जिले में प्रतिमाह निर्धारित तिथि पर युवा संगम का आयोजन किया जा रहा है। इस अभिनव पहल के तहत रोजगार दिवस, रोजगार मेला और अप्रेंटिसशिप मेले को एकीकृत कर युवाओं के लिए एक ही स्थान पर विभिन्न अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। रोजगार संचालनालय, कौशल विकास संचालनालय तथा एमएसएमई विभाग के समन्वित प्रयास से युवाओं को उनकी योग्यता और रुचि के अनुरूप रोजगार, प्रशिक्षण और स्वरोजगार के विकल्प उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

विश्वस्तरीय चिकित्सा, अत्याधुनिक तकनीक, अनुभवी विशेषज्ञ एवं 100 बिस्तरों के साथ
गैस्ट्रोकेयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
में **लिवर, पेन्क्रियाज, पित्ताशय, पेट, आँत, हर्निया, एपेंडिक्स, पाइल्स, फिशर, किडनी, कैंसर एवं कैंसर सर्जरी, स्त्री रोग, मूत्र रोग, मधुमेह, हार्मोन संबंधी रोग तथा मोटापे की सर्जरी** के उन्नत उपचार की सुविधा उपलब्ध है।

हमारी प्रमुख विशेषज्ञ सुविधाएँ
Advanced Endoscopy Centre
• ESG • POEM • ERCP • EUS
• Capsule Endoscopy
• Double-Balloon Enteroscopy
Ultra-Modern Modular OT with 3D Laparoscopic System
• GI • Gynae • Urology • Cancer Surgery
Hi-Tech Radiology Unit
• CT Scan • Color Doppler • Fluoroscopy
Advanced Pathology Department
GI Physiology Lab
• Advanced Manometry • pHmetry
• H. Pylori Breath Test

मध्यप्रदेश में पहली बार अत्याधुनिक तकनीकें

FibroScan Echosens Expert 630: लिवर एवं स्प्लीन की दर्दरहित जाँच • बायोप्सी का Non-invasive विकल्प
SpyGlass System: पित्त नली की सटीक जाँच एवं उपचार • हाई-डेफिनिशन विज़ुअल डायग्नोसिस
Holmium Laser Technology: पित्त की नली एवं किडनी की पथरी का ऑपरेशन रहित इलाज

BIG Gastrocare Multi Speciality Hospital
E-3/120, 121, अरेरा कॉलोनी भोपाल
फोन: 0755-4055123, 4701444
हेल्पलाइन: 9300 951 215

जन-अपेक्षाओं को पूर्ण करना ही जनप्रतिनिधियों का मुख्य ध्येय: गौर

गोविंदपुरा के वार्ड 64 में 98 लाख रुपये के विकास कार्यों का किया भूमि-पूजन

भोपाल मध्य स्वर्णिम।

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा कि नागरिकों की अपेक्षाओं को पूर्ण करना तथा उनकी समस्याओं का स्थाई समाधान निकालना ही जनप्रतिनिधियों की वास्तविक प्रतिबद्धता है।

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर सोमवार को गोविंदपुरा क्षेत्र के विभिन्न विकास एवं बुनियादी निर्माण कार्यों के भूमिपूजन समारोह को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जन-जन की सुविधाओं के विस्तार और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य कर रही है। कार्यक्रम में अयोध्या एक्सटेंशन

कॉलोनी में राजा मेडिकल स्टोर के पास 43 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाली सीसी सड़क तथा लेक सिटी कॉलोनी की मंदिर वाली गली में 33 लाख रुपये की लागत के सीसी सड़क निर्माण कार्य का विधि-विधानपूर्वक शुभारंभ किया गया। इसके अतिरिक्त भेल नगर स्थित अर्धनारीश्वर शिव मंदिर परिसर में 6 लाख रुपये की लागत से कल्चरल हॉल निर्माण, मानक विहार में सी-3 फिटनेस क्लब के समीप 10 लाख रुपये की लागत से आरसीसी नाली तथा जेपी कॉलोनी में हनुमान मंदिर के पास 6 लाख रुपये की लागत से आरसीसी नाली निर्माण कार्य का भी भूमि - पूजन हुआ।

राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने निर्माण एजेंसियों एवं विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वीकृत समस्त निर्माण कार्यों को तय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए, जिससे क्षेत्रवासियों को शीघ्र इन सुविधाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिल सके।